मनदीप कौर, डायरेक्टर

पढ़ें भारत हर ख़बर सच के साथ

राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र

आज तक आमने-सामने

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर | मुल्य : 5 रुपए

Email : aajtakaamnesaamne.in@gmail.com

RNI No-Punhin2013/54688 1-15 February 2026

एस. के. सक्सैना, मुख्य संपादक

साल 2026 / संपादक एसके सक्सैना / www aajtakaamnesaamne.com / Help Line 9878552070

नेशनल मीडिया ग्रुप आज तक आमने-सामने का स्टेट लेवल फंक्शन करवाया गया

स्पीकर कुलतार सिंह संधवा स्पेशल चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए

मनदीप कौर

जालंधर, नेशनल मीडिया ग्रुप आज तक आमने–सामने अपनी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से नाम कमा रहा है। पिछले सालों की तरह इस बार भी मीडिया ग्रुप की डायरेक्टर मैडम मंदीप कौर और चीफ एडिटर एस.के. सक्सेना की पूरी टीम ने जालंधर में स्टेट लेवल संस्कृत फंक्शन ऑर्गनाइज़ किया। पंजाब विधानसभा स्पीकर एस. कुलतार सिंह संधवा इस फंक्शन में स्पेशल चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, संत समाज, रिलीजियस, सोशल और मीडिया ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव, हाई पर्सनैलिटीज, आम और खास, जाने–माने क्लासिकल म्यूजिशियन, सूफी और फोक सिंगर्स के अलावा अलग–अलग फील्ड में माहिर लोग खास तौर पर पहुंचे और फंक्शन की शान बढ़ाई। फंक्शन में आए आर्टिस्ट्स ने अपने स्टाइल और इंटरेस्टिंग आर्ट से माहौल को बहुत मनमोहक बना दिया। पंडाल में मौजूद ऑडियंस ने इसका खूब मज़ा लिया। बेस्ट परफॉर्मर्स को स्टेट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद, माननीय चीफ गेस्ट ने मीडिया ग्रुप ऑफ़ ऑर्गनाइज़ेशन्स की स्पेशल गिफ्ट+ डायरेक्टरी और स्टिकर्स रिलीज़ किए। मीडिया के चीफ एडिटर, एस.के. सक्सेना ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि बड़ी मेहनत से तैयार की गई उक्त डायरेक्टरी आज लोगों के सामने पेश की जा रही है। वह डायरेक्टरी तैयार करने के लिए सपोर्टिंग ग्रुप के सदस्यों का दिल से धन्यवाद करते हैं। संगत राम ने स्टेज सेक्रेटरी की भूमिका बहुत अच्छे से निभाई। मीडिया ग्रुप की डायरेक्टर, मंदीप कौर, और चीफ एडिटर और मैनेजर, एस.के. सक्सेना ने उक्त समारोह को यादगार बनाने के लिए सभी सहयोगियों का धन्यवाद किया।

पंजाब विरोधी ताकतों के दुष्प्रचार पर भरोसा न करे–मुख्यमंत्री मान

हर परिवार को 10 लाख रुपये तक कैशलैस इलाज देने की व्यवस्था

एस. के. सक्सैना

चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पंजाबवासियों से अपील की कि राज्य सरकार द्वारा हर परिवार के लिए शुरू की गई 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के बारे में पंजाब विरोधी ताकतों द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार से गुमराह न हों। एक वीडियो संदेश के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, 卐पंजाब सरकार ने लोक भलाई वाली इस प्रमुख योजना की शुरुआत की है ताकि पंजाब के हर नागरिक, खास तौर पर समाज के कमजोर वर्गों को कैशलेस इलाज तक सीधी पहुंच मिल सके।卐 इस पहल के बारे में बताते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, 卐लोगों को व्यापक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' शुरू की है, जो देश में अपनी तरह की पहली योजना है। इसके तहत पंजाब का हर परिवार 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करवा सकता है।卐 इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 卐यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि पंजाब व्यापक स्तर पर मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह योजना लोगों पर वित्तीय बोझ को काफी कम करेगी और साथ ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सुनिश्चित करेगी।卐 इस योजना में रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी देते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, 卐इस ऐतिहासिक कदम का उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों को कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। सभी सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और अन्य नागरिक स्वास्थ्य कार्ड के लिए पात्र हैं। यह स्वास्थ्य कार्ड सुविधा केंद्रों और कॉमन सर्विस सेंटरों से या आधार कार्ड या वोटर कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। लोगों से मिल रहे उत्साह का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना का पंजाब के लोगों ने भरपूर स्वागत किया है और लोग इस योजना का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल ने उन परिवारों को बड़ी राहत पहुंचाई है, जिन्हें पहले बीमारी के इलाज का भारी खर्च अपनी जेब से देना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने भ्राम जानकारी फैलाने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ पंजाब विरोधी ताकतें, जो नहीं चाहतीं कि राज्य के लोगों को ऐसी सुविधाएं मिलें, जानबूझकर इस प्रमुख योजना के बारे में झूठ फैला रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि विपक्षियों द्वारा योजना को लेकर की जा रही बेतुकी बयानबाजी का मकसद लोगों को इस योजना से सिर्फ निराश करना है, जो पूरी तरह से गैर–वाजिब और अनुचित है। अस्पतालों को पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने इस योजना के तहत अधिक से अधिक निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है और इस योजना के तहत सरकार ने लगभग 2,600 बीमारियों और इलाज सेवाओं के लिए दरें निर्धारित की हैं। भुगतान विधि के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अस्पतालों को आपसी सहमति से तय दरों के अनुसार भुगतान करेगी, चाहे वे अस्पताल किसी बीमारी या इलाज सेवा के लिए बाहर के व्यक्तियों से कितनी भी अधिक राशि वसूल रहे हों। अस्पतालों की जवाबदेही के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के तहत सूचीबद्ध सभी अस्पताल सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर इलाज देने के लिए बाध्य हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि लाभार्थियों को कैशलेस इलाज मिले। योजना के बारे में किसी भी तरह की गलत जानकारी को सीधे तौर पर खारिज करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अस्पतालों को सरकार द्वारा सीधा भुगतान किया जाएगा और लाभार्थियों से एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। उन्होंने पंजाब विरोधी ताकतों द्वारा इस योजना के संबंध में गुमराह करने वाली और गलत तस्वीर पेश करने की कोशिशों को सिरे से नकारते हुए लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील की। योजना के लाभों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत लाभार्थियों के लिए इलाज सेवाएं कैशलेस हैं और अस्पतालों द्वारा मरीजों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसी ताकतों से सावधान रहना चाहिए जो बेबुनियाद अफवाहें फैलाकर जनहित को नुकसान पहुंचाने पर तुली हुई हैं। उन्होंने कहा कि मैं समूह पंजाबियों से अपील करता हूं कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। योजना के तहत इलाज सेवाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने ठोस व्यवस्था बनाई है जिसके तहत अस्पताल में दाखिले से लेकर जांच या टेस्ट, इलाज और अस्पताल से छुट्टी तक की पूरी इलाज प्रक्रिया कैशलेस रहेगी उल्लंघन के संबंध में स्पष्ट चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई अस्पताल इस योजना के तहत किसी मरीज से पैसे की मांग करता है तो तुरंत सरकार को शिकायत दर्ज करवाई जाए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ऐसे गलत कामों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी अस्पताल के खिलाफ सख्त, दंडात्मक और मिसाली कार्रवाई करेगी।

मोदी ने की जीत के लिए तारिक रहमान को बधाई दी

कहा–भारत हमेशा बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा

नई दिल्ली (एजंसी)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश चुनाव पर पहला बयान सामने आया है। उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की बंपर जीत के लिए इसके चेयरमैन तारिक रहमान को बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा-卐मैं श्री तारिक रहमान को बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने के लिए अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। यह जीत बांग्लादेश के लोगों द्वारा आपके नेतृत्व में रखे गए गहन विश्वास को दर्शाती है। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में निरंतर खड़ा रहेगा। मैं आपके साथ मिलकर हमारी बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम करने का इंतजार कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पोस्ट के बाद भारत–बांग्लादेश के संबंधों में सुधार की उम्मीद की जा रही है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के बीमार होने के दौरान उनके स्वास्थ्य के लेकर गहरी चिंता जाहिर की थी और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी। बाद में खालिदा के निधन पर गहरा दुख जाहिर किया था। इसे बांग्लादेश के साथ तनावपूर्ण संबंधों में सुधार के लिए एक अहम संकेत माना जा रहा है। पीएम मोदी ने अब बीएनपी की ऐतिहासिक जीत और तारिक रहमान के नेतृत्व के लिए उनको बधाई दी है। अगस्त 2024 से पहले तक शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहने के दौरान भारत–बांग्लादेश के संबंध सबसे मजबूत स्थिति में रहे। मगर जुलाई–अगस्त में एक छात्र आंदोलन के जरिये शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को सत्ता से बेदखल कर दिया गया।

पंजाब सरकार ने पंजाब क्रिकेट लीग को दी मंजूरी

आई.पी.एल. की तर्ज पर करवाई जाएगी पंजाब क्रिकेट लीग, जिला और क्षेत्रीय टीमें की जाएंगी शामिल

डा. सुभाष चंद्र शर्मा

चंडीगढ़, पंजाब की खेल विरासत बहाल करके नशों को खत्म करने के दृढ़ संकल्प के तहत भगवंत मान सरकार ने आज पंजाब क्रिकेट लीग (पी.सी.एल.) की शुरुआत को मंजूरी दे दी है। इस लीग के तहत खेलों को एक आउटरीच कार्यक्रम की बजाय नौजवानों के सशक्तिकरण के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप के रूप में देखा जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग (आई.पी.एल.) की तर्ज पर जिला और क्षेत्रीय स्तर पर टीमें बनाकर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) तथा पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पी.सी.ए.) के सहयोग से करवाई जाने वाली इस लीग का उद्देश्य नौजवान प्रतिभा की पहचान करना, तैयार करना और पेशेवर राह पर ले जाना है। इसके साथ ही इसका उद्देश्य खेलों में जिला और राज्य–स्तरीय लीगों का एक व्यापक इको–सिस्टम स्थापित करना है ताकि राज्य के नौजवानों को नशों से दूर रखकर अनुशासन, नए मौकों और राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व की ओर ले जाया जा सके। मीटिंग में लिए गए कुछ फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, 卐आज चंडीगढ़ में खेल और युवक सेवाएं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए मीटिंग की, जिसमें राज्य भर में खेल संस्कृति को उत्साहित करने पर विचार–विमर्श किया गया। सभी अधिकारियों को हिदायत की गई कि वे एक स्वस्थ समाज की सृष्टि के उद्देश्य से नौजवानों को खेलों में हिस्सा लेने के लिए उत्साहित करने में अपना अधिकतम योगदान दें। सरकार द्वारा राज्य में खेल संस्कृति बहाल करने और राज्य भर के नौजवानों को खेल मैदानों से जोड़ने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं।卐 खेल विभाग की समीक्षा मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य भर से नौजवान प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के तालमेल से पंजाब क्रिकेट लीग करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी पहलकदमियों ने विश्व क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, 卐इमरान खान और अर्जुन राणातुंगा जैसे क्रिकेटरों ने ऐसी पहलकदमियों के माध्यम से विश्व क्रिकेट को कई प्रसिद्ध खिलाड़ी दिए और यह लीग पंजाब को क्रिकेट प्रतिभा की नर्सरी के रूप में उभारने में बहुत मदद करेगी। प्रस्तावित लीग ढांचे के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह लीग इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर करवाई जाएगी और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए सभी जिलों और माझा, दोआबा तथा मालवा जैसे भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर टीमें बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह लीग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट टूर्नामेंटों के लिए क्रिकेटरों का प्रतिभाशाली पूल पैदा करने में मदद करेगी। इसके साथ ही उन्होंने राज्य भर में अन्य खेलों को उत्साहित करने की जरूरत पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, खो–खो और कबड्डी जैसी खेलों के लिए भी जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय लीग टूर्नामेंट करवाए जाने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार अच्छी तरह प्रशिक्षित और प्रतिभाशाली खिलाड़ी पैदा करने के लिए ठोस अभियान पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य यह यकीनी बनाना है कि अधिक से अधिक पंजाबी खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय खेल मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व करें। पंजाब की अमीर खेल विरासत के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य में खेल प्रतिभा का भंडार है और सरकार इसे बढ़ने–फूलने में मदद करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि पंजाब के नौजवानों में अथाह खेल प्रतिभा है और राज्य सरकार खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा लेकर देश के लिए तगमे जीतने योग्य बनाने के खातिर कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि खेल नौजवानों को आगे बढ़ने और राज्य का नाम रौशन करने के लिए सही दिशा प्रदान करते हुए हमारे नौजवानों को बुलंदियों छूने और अपनी शख्सियत निखारने के बेमिसाल मौके देते हैं। भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि सरकार खेल के क्षेत्र में राज्य की पुरातन शान बहाल करने के लिए दृढ़ है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार खेलों में पंजाब की शान को पुनर्जीवित करने के लिए वचनबद्ध है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही।

संपादकीय

तंबाकू का इस्तेमाल

दुनिया भर में, तंबाकू का इस्तेमाल अब सिर्फ़ निजी आदत या सामाजिक व्यवहार का मामला नहीं रहा, बल्कि यह एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन के अनुसार, दुनिया भर में हर साल तंबाकू से जुड़ी बीमारियों की वजह से लगभग 8 मिलियन लोगों की मौत होती है। यह आंकड़ा किसी युद्ध, प्राकृतिक आपदा या महामारी से कम नहीं है। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में तंबाकू का असर और भी गंभीर है, जहाँ हर साल लाखों लोग कैंसर, दिल की बीमारी, फेफड़ों की बीमारियों और दूसरी दिक्कतों की वजह से समय से

पहले मर जाते हैं। मैं मानता हूँ कि तंबाकू सिर्फ़ शरीर को ही नहीं, बल्कि देश की इकॉनमी, सामाजिक ढांचे और नैतिक मूल्यों को भी बर्बाद कर रहा है। ऐसे में, यह सवाल बहुत ज़रूरी हो जाता है- क्या सिर्फ़ टैक्स बढ़ाना और चेतावनी वाले मैसेज काफ़ी हैं? या भारत में तंबाकू पर पूरी तरह और सख़्त कानूनी बैन लगाने का समय आ गया है? तंबाकू का सेहत पर असर कई तरह का और जानलेवा होता है। स्मोकिंग और स्मोकलेस तंबाकू दोनों ही शरीर के लगभग हर अंग पर असर डालते हैं। फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज़ जैसी बीमारियाँ सीधे तौर पर तंबाकू के इस्तेमाल से जुड़ी हैं। भारत में मुंह के कैंसर के मामले बहुत ज़्यादा हैं, जिसका मुख्य कारण गुटखा, पान मसाला और दूसरे स्मोकलेस तंबाकू प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल है। यह स्थिति सिर्फ़ एक्टिव कंज्यूमर्स तक ही सीमित नहीं है। पैसिव स्मोकिंग, या सेकंड-हैंड स्मोक के संपर्क में आने से भी बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों को गंभीर हेल्थ रिस्क होता है। प्रेग्नेंट महिलाओं पर इसका असर भ्रूण के विकास में रुकावट डाल सकता है, जिससे कम वज़न वाले बच्चे या जन्म से ही डिफेक्ट हो सकते हैं। तंबाकू इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है, जिससे टीबी जैसी इंफेक्शन वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इस तरह, तंबाकू एक महामारी है जो नॉन-कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल, दोनों तरह की बीमारियों में योगदान देती है। दोस्तों, अगर हम भारत में मौजूदा तंबाकू कंट्रोल कानूनों पर गौर करें, जैसे सिगरेट और अन्य तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्ट 2003, जो पब्लिक जगहों पर स्मोकिंग पर बैन लगाता है, एडवरटाइजिंग पर बैन लगाता है, और पैकेजिंग पर हेल्थ वॉर्निंग देता है। शहर में कई कानून हैं, और कई राज्यों ने तंबाकू पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा, भारत ने WHO फेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल पर साइन किया है, जो दुनिया भर में तंबाकू कंट्रोल के लिए एक अहम ट्रीटी है। इसके बावजूद, ज़मीनी स्तर पर तंबाकू की उपलब्धता, पहुंच और सामाजिक स्वीकृति में कोई कमी नहीं आई है। गुटखा और बीड़ी गांव और शहर दोनों इलाकों में आसानी से मिल जाते हैं। ये छोटी दुकानों और पान ठेलों पर खुलेआम बेचे जाते हैं, जिससे टीनएजर्स और युवा इनके संपर्क में आते हैं। इससे पता चलता है कि मौजूदा सिस्टम में सख्ती से लागू करने और पूरी तरह से रोक लगाने की कमी है। दोस्तों, साथी स्मोकिंग करने वाले, सामाजिक नज़रिए से तंबाकू के गहरे और लंबे समय तक चलने वाले असर को समझते हुए भी, अक्सर पारिवारिक तनाव, पैसे के दबाव और सेहत की समस्याओं के कारण अकेलेपन का अनुभव करते हैं। जब परिवार का कमाने वाला तंबाकू से जुड़ी बीमारी से पीड़ित होता है, तो पूरा परिवार पैसे और मानसिक परेशानी में डूब जाता है। बीड़ी इंडस्ट्री जैसे सेक्टर में काम करने वाले लाखों मज़दूर, खासकर महिलाएं और बच्चे, बहुत खराब हालात में काम करते हैं। वे खुद तंबाकू की धूल और केमिकल के संपर्क में आने के कारण सेहत के खतरों का सामना करते हैं। यह स्थिति सामाजिक असमानता को और गहरा करती है, क्योंकि तंबाकू इंडस्ट्री का बोझ मुख्य रूप से गरीबों और अनपढ़ लोगों पर पड़ता है। जो लोग पहले से ही आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वे तंबाकू पर खर्च करके और गरीबी में चले जाते हैं। इस तरह, तंबाकू सिर्फ़ हेल्थ का मुद्दा ही नहीं है, बल्कि सोशल जस्टिस का भी सवाल है। दोस्तों, आइए तंबाकू इंडस्ट्री की भूमिका को नैतिक नज़रिए से समझें। जब यह साफ़ हो जाता है कि तंबाकू खाने से मौत और गंभीर बीमारियाँ होती हैं, तो तंबाकू का लगातार प्रोडक्शन और मार्केटिंग नैतिक सवाल खड़े करता है। इंडस्ट्री का मुख्य मकसद मुनाफ़ा कमाना है, लेकिन यह मुनाफ़ा इंसानी जान की कीमत पर हासिल किया जाता है। युवाओं को आकर्षित करने के लिए इनडायरेक्ट एडवरटाइजिंग, फ़िल्मों के सीन में स्मोकिंग को बढ़ावा देना और रंगीन पैकेजिंग जैसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जाता है। टीनएज में शुरू होने वाली लत ज़िंदगी भर की लत बन जाती है, जो आने वाली पीढ़ियों की प्रोडक्टिविटी और हेल्थ को कमज़ोर करती है। तंबाकू की खेती और प्रोडक्शन भी पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। यह अनुमान लगाया गया है कि तंबाकू पैदा करने के लिए एक पेड़ काटा जाता है। तंबाकू की खेती में केमिकल फ़र्टिलाइज़र और पेस्टीसाइड के ज़्यादा इस्तेमाल से ज़मीन और पानी प्रदूषित होता है। सिगरेट के टुकड़े प्लास्टिक-बेस्ड होते हैं और लंबे समय तक पर्यावरण में रहते हैं, जिससे इकोसिस्टम पर असर पड़ता है। इस तरह, तंबाकू सिर्फ़ इंसानी हेल्थ के लिए ही नहीं, बल्कि पर्यावरण की नैतिकता के लिए भी खतरा है।

आज तक आमने सामने

RNI NO -PUNHIN0/2013/54688

Printed by Mandeep Kaur, Published by Mandeep Kaur, Owned by Mandeep Kaur & Printed at Dashmash Printers 178-179 Ranjit Nagar, Jalnadhar City, Published 87 Ranjit Nagar Near Bus Stand, Jalandhar, Punjab

Editor Surinder Kumar (SK Saxena)

Responsible for selection of News under the PRB ACT.
All Rights Reserved Reproduction in whole or in Part without Permission in Prohibited, All disputes shall be settled at Jalandhar Jurisdiction only
Faxt No. : 0181-5024001, Conact No : 0181-5077100

आवश्यक सूचना

आज तक आमने-सामने का इस समाचार पत्र में मुद्रित वज्ञापनों (डिस्पले/क्लासीफाईड) के तथ्यों सबंधी कोई दायित्व नहीं है। महारा समाचार पत्र इनको सत्यापित नहीं करता। पाठकों से अनुरोध है कि वे इन विज्ञापनों पर कार्यवाही करने से पूर्व सभी तथ्यों की स्वयं पुष्टि कर लें। -प्रधान संपादक

चौहाल जंगल सफारी और बोटिंग से पर्यटकों ने लिया कुदरत का आनंद

सोलिस ठरोली में नाइट कैंपिंग और ओपन माइक ने बनाई यादगार शाम

एस. के. सक्सैना

होशियारपुर, होशियारपुर में आयोजित नेचर फेस्ट-2026 पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए प्रकृति, रोमांच और संस्कृति का अद्भुत संगम बनकर उभर रहा है। दो दिनों के दौरान विभिन्न गतिविधियों में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर कुदरत की गोद में समय बिताया। शनिवार सुबह पर्यटकों ने चौहाल में जंगल सफारी और बोटिंग का आनंद लेते हुए प्राकृतिक सौंदर्य को करीब से महसूस किया। रविवार सुबह ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग तथा ऑफ-रोडिंग गतिविधियों के माध्यम से प्रतिभागियों ने प्रकृति के विविध रंगों को जाना। शनिवार शाम सोलिस ठरोली में आयोजित नाइट कैंपिंग विशेष आकर्षण रही। पर्यटकों ने खुले आसमान के नीचे कैंपिंग का आनंद लिया, जबकि ओपन माइक और संगीत प्रस्तुतियों ने माहौल को यादगार बना दिया। रविवार सुबह लाजवंती स्पोर्ट्स स्टेडियम से कुकानेट-देहरियां तक ऑफ-रोडिंग एडवेंचर आयोजित किया गया। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न स्टालों का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया।

डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने कहा कि 卐नेचर फेस्ट का उद्देश्य पर्यटकों को होशियारपुर की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन संभावनाओं से परिचित कराना है। यह आयोजन रोमांच और मनोरंजन के साथ लोगों को प्रकृति के करीब लाने की महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि 16 फरवरी को पर्यटकों को उन्नति,

फैप्रो एवं सिट्रस इकाइयों का औद्योगिक भ्रमण के अलावा

मियावाकी साइट विजिट, वन चेतना पार्क में किड्स कार्निवल, लाजवंती स्टेडियम में सांस्कृतिक गतिविधियां करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि 17 फरवरी को विभिन्न प्रस्तुतियां एवं प्रतियोगिताओं के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रसिद्ध पंजाबी गायक गुरदास मान की सिंगर नाइट आकर्षक का केन्द्र रहेगी। उन्होंने बताया कि 17 को ही बम्बूघाट-2 की स्टारकास्ट भी विशेष तौर पर पहुंच रही है, जिसमें सिम्मी चाहल, एम्मी विर्क, करमजीत अनमोल दर्शकों से रूबरू होंगे।

डिप्टी कमिश्नर ने जिला वासियों से अपील की कि वे परिवार सहित इस अनूठे आयोजन में भाग लेकर पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास को सफल बनाएं। इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) निकास कुमार, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (सामान्य) अमरबीर कौर भुल्लर, एसडीएम मुकेरियां ओएशी मंडल, नगर निगम कमिश्नर ज्योति बाला, एसडीएम होशियारपुर गुरसिमरनजीत कौर, सहायक कमिश्नर परमप्रीत सिंह, अधिक सहायक कमिश्नर गुरप्रीत कौर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

पंजाब शिक्षा क्रांति के तहत खस्ताहाल मसौल के सरकारी स्कूल को मॉडल स्कूल में बदला : हरजोत सिंह बैंस

खस्ताहाल होने के कारण सुर्खियों में रहने वाला स्कूल शिक्षा के पुनरुत्थान का प्रत्यक्ष प्रमाण-हरजोत सिंह बैंस

डा. सुभाष चंद्र शर्मा

चंडीगढ़, -पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज गांव मसौल के सरकारी स्कूल में किए गए शानदार बदलाव पर प्रकाश डाला, जो पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट-1, चंडीगढ़ से महज 20 मिनट की दूरी पर स्थित है। श्री बैंस ने कहा कि यह स्कूल अब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की 卐पंजाब शिक्षा क्रांति卐 के तहत जनता की शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने की प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लगभग दो साल पहले स्कूल की स्थिति को याद करते हुए, शिक्षा मंत्री ने कहा, 卐जब मैंने लगभग दो साल पहले मसौल गांव के सरकारी स्कूल का दौरा किया था, तो स्कूल की हालत बहुत ही दयनीय थी। इमारत खस्ताहाल थी, क्लासरूम टूटे हुए थे और विद्यार्थियों को पढ़ने-लिखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। मसौल गांव कभी अपने सरकारी स्कूल की दयनीय स्थिति के कारण अखबारों और टेलीविजन चैनलों की सुर्खियों में रहता था। श्री बैंस ने कहा, 卐मैं उस समय इस स्कूल का दौरा किया

था और मैं इस स्कूल में आने वाला पहला शिक्षा मंत्री था। मैंने जो देखा, वह बहुत दुखद था। यहां सिर्फ बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण की ही जरूरत नहीं थी, बल्कि विद्यार्थियों और समुदाय के विश्वास को बहाल करने की भी आवश्यकता थी। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि स्थिति का जायजा लेने के बाद, उन्होंने स्कूल को एक मॉडल स्कूल में बदलने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा, 卐मेरे दौरे के बाद, स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा क्रांति मुहिम के तहत व्यापक विकास कार्य शुरू किए। आज, स्कूल को एक नई इमारत, बेहतर क्लासरूम, बेहतर सुविधाएं और सीखने का अनुकूल वातावरण प्रदान करके पूरी तरह बदल दिया गया है।卐 अकादमिक प्रगति को उजागर करते हुए उन्होंने कहा, 卐विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है, जो केंद्रित हस्तक्षेप के सकारात्मक परिणामों को दर्शाता है। यह स्कूल अब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की जनता की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने कहा, 卐पड़ोसी गांव, जो कभी स्कूल की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते थे, अब मसौल का दौरा करके इसकी तब्दीली की प्रशंसा करते हैं।सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, 卐पंजाब शिक्षा क्रांति एक समग्र लहर है जिसका उद्देश्य अकादमिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देना, बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना और जनता की शिक्षा में विश्वास को बहाल करना है। पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करना जारी रखेगी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हर बच्चे को एक सम्मानजनक और अनुकूल माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए।

गैंगस्टरां ते वार' का 25वां दिन-पंजाब पुलिस ने 702 स्थानों पर छापेमारी की; 232 गिरफ्तार

मनदीप कौर

चंडीगढ़, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत शुरू की गई निर्णायक 'गैंगस्टरां ते वार मुहिम के 25वें दिन, पंजाब पुलिस ने आज पूरे राज्य में गैंगस्टरों के साथियों से जुड़े पहचाने गए और मैप किए गए ठिकानों पर 702 छापेमारियां कीं। जानकारी के अनुसार, 卐गैंगस्टरां ते वार卐 - पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए शुरू की गई निर्णायक जंग - 20 जनवरी, 2026 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा शुरू की गई थी। इसके तहत सभी जिलों की पुलिस टीमों द्वारा एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से पूरे राज्य में विशेष कार्रवाइयां की जा रही हैं। इस मुहिम के 25वें दिन, पुलिस टीमों ने 232 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 3 हथियार बरामद किए। इसके साथ ही मुहिम की शुरुआत से अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 9244 हो गई है। इसके अलावा 89 व्यक्तियों के खिलाफ रोकथाम कार्रवाई की गई, जबकि 165 व्यक्तियों का सत्यापन किया गया और पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस टीमों द्वारा कार्रवाई के दौरान 7 भगोड़े अपराधियों

पुलिस टीमों ने 89 व्यक्तियों के खिलाफ रोकथाम कार्रवाई की, 165 को तस्दीक के बाद रिहा किया

(पीओ) को भी गिरफ्तार किया गया है। वांछित अपराधियों/गैंगस्टरों के बारे में जानकारी और अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना देने के लिए लोग गुप्त रूप से एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम 卐युद्ध नशियां विरुद्ध卐 के 350वें दिन भी जारी रखते हुए आज 96 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 3.1 किलो हेरोइन, 7 किलो भुक्की, 640 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 58,050 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इससे मात्र 350 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 49,602 हो गई है। नशा छुड़ाने की मुहिम के हिस्से के रूप में, पंजाब पुलिस ने आज 41 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास के इलाज के लिए राजी किया है।

कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत ने सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को सम्मान राशि के चैक सौंपे

विधान सभा शाम चौरासी की 59 ग्राम पंचायतों को 2.95 करोड़ रुपए किए जारी

रमन कुमार

होशियारपुर, कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने आज बीडीपीओ कार्यालय होशियारपुर-1 में विधानसभा शाम चौरासी क्षेत्र की 59 ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों हेतु 5-5 लाख रुपए की राशि के चैक वितरित किए। उन्होंने बताया कि यह राशि उन पंचायतों को प्रदान की गई है, जहां हालिया ग्राम पंचायत चुनावों में सर्वसम्मति से पंचायतों का चयन किया गया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा घोषणा की गई थी कि सर्वसम्मति से चुनी गई पंचायतों को गांव के समग्र विकास के लिए विशेष सम्मान राशि दी जाएगी। सरकार की इसी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए पंचायतों को यह राशि जारी की गई है। डॉ. रवजोत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा शाम चौरासी क्षेत्र में कुल 267 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 59 पंचायतों में सर्वसम्मति से प्रतिनिधि चुने गए। इनमें 15 पंचायतें ब्लॉक भूंगा तथा 44 पंचायतें होशियारपुर ब्लॉक-1 से संबंधित हैं। प्रत्येक पंचायत को 5-5 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। इस प्रकार विधानसभा क्षेत्र शाम चौरासी के लिए कुल 2 करोड़ 95 लाख रुपए की विकास राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि यह

सम्मान राशि गांवों में बुनियादी ढांचे के सुधार, स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था, गलियों-नालियों के निर्माण, सामुदायिक सुविधाओं तथा अन्य जनहित कार्यों पर खर्च की जाएगी। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की कि राशि का पारदर्शी और जनहित में उपयोग सुनिश्चित किया जाए। कैबिनेट मंत्री ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अपना वादा पूरा कर ग्रामीण विकास को नई गति दी है। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य, बीडीपीओ भूंगा, बीडीपीओ होशियारपुर-1 तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

नेचर फेस्ट के दूसरे दिन खरीदारी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दिखा जलवा

लाजवंती स्पोर्ट्स स्टेडियम में उमड़ी लोगों की भीड़

पंकज

होशियारपुर, नेचर फेस्ट होशियारपुर के दूसरे दिन लाजवंती स्पोर्ट्स स्टेडियम में भारी संख्या में लोग पहुंचे और जमकर खरीदारी की। इस दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने भी लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। मेले में स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, जैविक उत्पादों और अन्य सामानों की विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। लोगों ने तरह-तरह के स्टॉलों पर जाकर खरीदारी की और स्थानीय उत्पादों को खूब सराहा। खाने-पीने के स्टॉलों पर भी काफी भीड़ देखी गई, जहां पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठाया गया। दूसरे दिन की खासियत सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे, जिनमें लोकनृत्य, गायन प्रतियोगिता और रंगारंग प्रस्तुतियां शामिल थी। पंजाबी भांगड़ा और गिद्दा की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समां बांध दिया, जिससे दर्शकों का उत्साह चरम पर था। ज़िला रेडक्रॉस सोसायटी का विंग्स प्रोजेक्ट का स्टाल भी आकर्षण का केंद्र बना रहा। डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने बताया कि नेचर फेस्ट का उद्देश्य न केवल लोगों का मनोरंजन करना है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना भी है। उन्होंने बताया कि ' नेचर फेस्ट होशियारपुर' के माध्यम से प्रकृति की गोद में बसे होशियारपुर में पर्यटन की असीम संभावनाओं से लोगों को

रुबरु करवाना है भी है। डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने बताया कि 15 फरवरी को प्रसिद्ध गायक प्रभ गिल की सिंगर नाइट मुख्य आकर्षण रहेगी। उन्होंने बताया कि सिंगर नाईट में खुला प्रवेश है। इस लिए लोग अपने चहेते गायक को सुनने के लिए जरूर पहुंचे। इसके अलावा 15 को साइक्लोथॉन, तलवाड़ा में बर्ड वॉचिंग, फॉरेस्ट डिस्कवरी ट्रेल (ऑफ-रोडिंग व ट्रैकिंग), बोटिंग एवं ट्रेजर हंट का भी लोग लुत्फ उठा पाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में मेले में भाग लें और इस पहल को सफल बनाएं। उन्होंने बताया कि नेचर फेस्ट के दौरान लोगों के लिए खुला प्रवेश है और स्टेडियम में विभिन्न चीजों, कलाकृतियों और सामान की पेशकश करते हुए 100 के करीब स्टॉल लगे हैं।

पढ़ें भारत हर ख़बर सच के साथ

राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र

आज तक आमने-सामने

हरियाणा समाचार

Email : aajtakaamnesaamne.in@gmail.com

1-15 February 2026

मनदीप कौर, डायरेक्टर

एस. के. सक्सैना, मुख्य संपादक

साल 2026 / संपादक एसके सक्सैना / www aajtakaamnesaamne.com / Help Line 9878552070

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में उद्योग हितैषी नीतियों के साथ आगे बढ़ रहा हरियाणा: डॉ. अमित अग्रवाल

एस. के. सक्सैना

उद्योगों के लिए हरियाणा बेहतरीन कनेक्टिविटी और बाजार तक आसान पहुंच कर रहा प्रदान

चंडीगढ़, – हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने मजबूत आर्थिक आधार और उद्योग हितैषी नीतियों को रेखांकित करते हुए कहा कि हरियाणा देश के प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत' के विजन को धरातल पर उतारने के लिए तैयार है। हरियाणा निरंतर अपने निवेशकों के लिए बेहतर नीतियां बना रहा है और उन्हें लागू भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के मद्देनजर हरियाणा बेहतरीन कनेक्टिविटी और बाजार तक आसान पहुंच प्रदान करता है। डॉ. अग्रवाल शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उद्योग जगत के लीडर्स और हितधारकों का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा एक स्पष्ट रोडमैप के साथ आगे बढ़ रहा है, ताकि निवेश और उद्यम के लिए देश के सबसे आकर्षक गंतव्यों में अपनी स्थिति को और मजबूत किया जा सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में उद्योग हितैषी नीतियां बनाई जा रही है और प्रदेश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि बेहतर सकल घरेलू उत्पाद के साथ हरियाणा की विकास दर लगातार राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 1.3 प्रतिशत और आबादी का 2.1 प्रतिशत हिस्सा होने के बावजूद, राज्य देश के कुल जीएसटी संग्रह में लगभग 7.1 प्रतिशत का योगदान देता है। उन्होंने कहा कि यह हरियाणा की मजबूत आर्थिक नींव और उच्च मूल्य संवर्धन क्षमता का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में प्रति व्यक्ति आय की वास्तविक वृद्धि भी लगातार राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से 70 प्रतिशत से अधिक है। डॉ. अग्रवाल ने आगे कहा कि हरियाणा की भौगोलिक स्थिति उसकी सबसे बड़ी संरचनात्मक ताकतों में से एक है। देश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नजदीक स्थित होने के कारण हरियाणा बेहतरीन कनेक्टिविटी और बाजार तक आसान पहुंच प्रदान करता है। राज्य के सभी जिले राष्ट्रीय राजमार्गों या चार–लेन एक्सप्रेसवे से जुड़े हैं और कोई भी जिला गुरुग्राम या दिल्ली से तीन से चार घंटे से अधिक दूर नहीं है। इसके अलावा, पूरा राज्य तीन प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों–नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के 300 किलोमीटर के दायरे में आता है, जिससे वैश्विक बाजारों तक तेज पहुंच सुनिश्चित होती है। हरियाणा ने विभिन्न क्षेत्रों में मजबूत औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित किए हैं, जिनमें एनसीआर क्षेत्र में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहन क्लस्टर, अंबाला में मेडिकल डिवाइस, पानीपत में वस्त्र, बहादुरगढ़ में चमड़ा और फुटवियर, कई जिलों में फूड पार्क तथा उभरते उद्योगों को समर्थन देने के लिए आईएमटी सोहना में नई पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर शामिल है। डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार सरल नियमों, बेहतर आधारभूत संरचना और निवेशक केंद्रित प्रशासन के माध्यम से कारोबार सुगमता को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

निवेशकों के विश्वास, नीतियों में पारदर्शिता के ध्येय के साथ काम कर रहा हरियाणा: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से की मुलाकात

मनदीप कौर

चंडीगढ़, – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों के विश्वास, नीतियों में पारदर्शिता के ध्येय के साथ काम कर रही है। हरियाणा औद्योगिक निवेश के लिए सबसे बेहतर राज्यों में से एक है, जहां अनुकूल माहौल है। मुख्यमंत्री शनिवार को नई दिल्ली में निवेशकों से भेंट कर रहे थे। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के प्रतिनिधियों से प्रदेश में निवेश को लेकर मुलाकात की और उनकी आगामी योजना को जाना। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ऐसी नीतियों का निर्माण कर रही है, जिससे निवेशकों का अधिक से अधिक विश्वास उन पर बने। इसके साथ–साथ उनकी नीतियों में पारदर्शिता है। सरकारी अप्रूवल में कम से कम समय लगे और यह कार्य तेज रफ्तार से हो, इस तरह के लक्ष्य के साथ कार्य किया जा रहा है। यूरोपियन संघ की एमएसएम से हरियाणा की एमएसएमई से मैच मेकिंग की जाएगी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत और ईयू के बीच हुए समझौते से हरियाणा के उद्योगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने इसे लेकर हरियाणा–यूरोपियन वर्किंग संघ बनाने की घोषणा की है। इसका

मुख्य मकसद यूरोपियन संघ की एमएसएमई की हरियाणा की एमएसएमई के साथ मैच मेकिंग करवाना होगा ताकि उनके उद्योंगों की जो भी जरूरतें हैं, वो हमारे यहां के उद्योग पूरी कर सकें। इससे हरियाणा के उद्योंगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि विदेशी कंपनियों के पार्ट को चिह्नित करके हरियाणा में निर्माण कर रही कंपनियों के साथ जोड़ा जाएगा।

उद्योगों को निरंतर उपलब्ध करवाई जा रही जमीन–मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उद्योंगों को स्थापित करने के लिए एचएसाईआईडीसी निरंतर जमीन उपलब्ध करवा रहा है। अलग–अलग इंडस्ट्रियल जोन बनाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार 10 नई आईएमटी बना रही है। उन्होंने ऐसी कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की, जो हरियाणा में उद्योंगों के लिए जमीन तलाश कर रहे हैं।

जीसीसी पर जल्द पॉलिसी लाएगा हरियाण–मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज विश्वभर की कंपनियां अलग–अलग देशों में काम कर रही हैं। ऐसे में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) का रूझान तेजी से बढ़ा है। प्रदेश सरकार जल्द ही ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) के लिए नई पॉलिसी लाने जा रही है। इससे ऐसी कंपनियों के लिए आसानी होगी, जो हरियाणा में जीसीसी स्थापित करना चाहती है।

इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, महानिदेशक श्री यश गर्ग, एचएसआईआईडीसी के सीसीआई सुनील शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सुरक्षा बलों एवं शहीदों की बदौलत ही हमारा देश सुरक्षित है : आरती सिंह राव

डा. सुभाष चंद्र शर्मा

चंडीगढ़ , – हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि सुरक्षा बलों एवं शहीदों की बदौलत ही हमारा देश सुरक्षित है , इनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह बात पुलवामा आतंकी हमले में अपनी जान गंवाने वाले बहादुर सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज यहां कही। उन्होंने कहा कि गत 14 फरवरी 2019 को जम्मू–श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर दोपहर करीब 3 बजे आत्मघाती हमला हुआ था। इस

दर्दनाक घटना को याद करते हुए हर साल 14 फरवरी को देशभर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है और इस दिन को 'ब्लैक डे' के रूप में याद किया जाता है। आरती सिंह राव ने कहा कि उन 40 सुरक्षाकर्मियों का सर्वोच्च बलिदान देश की स्मृति में सदैव अंकित रहेगा और उनका त्याग प्रत्येक नागरिक को मजबूत व सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि वे खुद एक शहीद परिवार से ताल्लुक रखती हैं , इसलिए वे जानती हैं की भारत माता की रक्षा में दिए गए सर्वोच्च बलिदान के लिए केवल सैनिक का परिवार ही नहीं पूरे देश को फ़क्र होता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पुलवामा में शहीद हुए माँ भारती के इन वीर सपूतों का साहस, कर्तव्यनिष्ठा और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका अदम्य हौसला हमें यह संकल्प दिलाता है कि हम आतंकवाद और हिंसा के विरुद्ध एकजुट होकर दृढ़ता से खड़े रहें तथा राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोपरि रखें। उन्होंने आगे कहा कि पुलवामा का यह हमला केवल सुरक्षाबलों पर नहीं, बल्कि पूरे देश की आत्मा पर प्रहार था। किन्तु हमारे जवानों की शहादत ने भारत को और अधिक सशक्त, संगठित और संकल्पित बनाया है। देशवासियों की एकता ही आतंकवाद के विरुद्ध हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

विकसित भारत में रहेगी हरियाणा की महत्वपूर्ण भूमिका: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

रमन कुमार

मुख्यमंत्री बोले– निवेशकों की पहली पसंद बना हरियाणा, तेजी से हो रहा औद्योगिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास

चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2047 में विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है, इसे पूरा करने में हरियाणा की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। नई–नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री शनिवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। हरियाणा सरकार ने पिछले बजट में 10 नई आईएमटी बनाने की घोषणा की थी। इनमें से 6 आईएमटी पर तेजी से काम चल रहा है बाकि 4 आईएमटी का काम भी जल्द पूरा किया जाएगा। जीएसटी में प्रदेश पहले स्थान पर है। हरियाणा में रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर है कि साढ़े तीन से चार घंटे में एक कोने से दूसरे कोने में जाया जा सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट और हिसार एयरपोर्ट की सीधे कनेक्टिविटी है। इन सभी को ध्यान में रखकर निवेशक निरंतर हरियाणा में आ रहे हैं, इससे विकसित भारत में हरियाणा की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है।

हरियाणा ने हर क्षेत्र में बनाई पहचान–मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 1966 में जब हरियाणा– पंजाब से अलग होकर एक नया प्रदेश बना तो हर किसी को प्रदेश की तरक्की पर शक था लेकिन हरियाणा ने तेजी से तरक्की की और अपनी अलग पहचान बनाई। आज भारत की सेना में हर दूसरा जवान हरियाणा से है। खेलों में यदि भारत के मेडल आते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान हरियाणा के खिलाड़ियों का होता है। फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से 250 हरियाणा में काम कर रही हैं। आटोमोबाइल मैन्यूफैक्चिरिंग में हरियाणा देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश सरकार जल्द ही नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने वाली है। इससे और निवेशक प्रदेश की ओर आकर्षित होंगे।

प्लॉनिंग से स्थापित किया जा रहा इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर–मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐसी प्लॉनिंग के साथ स्थापित किया जा रहा है कि आने वाले 50 सालों तक कोई दिक्कत न आए। गन्नौर में फूट मंडी बनकर लगभग तैयार है। वहीं खारी बावली की ड्राई फूट मार्किट, मार्बल मार्किंग और अमृतसर की मजीद मार्किट को भी हरियाणा में स्थापित करने की योजना है। वहां के व्यापारियों ने हरियाणा में स्थापित होने वाली मंडी में आने के लिए रूचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा अब प्राकृतिक खेती में भी पहचान बनाएगा। वहीं पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हुए उन्होंने किसानों से पराली न जलाने का आह्वान किया। इसके बाद 95 प्रतिशत तक पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई। बेहतर पराली प्रबंधन के लिए माननीय न्यायालय ने प्रदेश का उदाहरण दिया है।

प्रधानमंत्री ने देश को बदलने का काम किया–हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 55 साल देश पर शासन किया जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महज 11 साल के शासन में देश की तस्वीर बदलने का काम किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 5 गुणा कम समय मिला लेकिन उन्होंने भारत को विकसित भारत की ओर ले जाने का काम किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा। प्रधानमंत्री ने भारत को 5वीं आर्थिक शक्ति बनाने का लक्ष्य रखा था, उन्होंने यह कर दिखाया। उनके नेतृत्व में सरकार हर पैमाने पर खरा उतरी है।

भारत–ईयू समझौते से होगा लाभ–मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा भारत और यूरोपियन संघ के साथ हुए भारत–यूरोपियन मुक्त व्यापार समझौते के बाद उन्होंने हरियाणा यूरोपियन व्यापार संघ की बैठक की। इसमें उन्होंने भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए, जिन्हें हरियाणा के आगामी बजट में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। गुरुग्राम के निचले इलाकों के लिए एक ड्रेन की प्लानिंग की गई है। वहीं पीने के पानी की समस्या के लिए ऐसी योजना तैयार की गई है कि गुरुग्राम को आने वाले 50 वर्षों तक कोई समस्या नहीं होगी।

इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल, महानिदेशक श्री यश गर्ग, एचएसआईआईडीसी के सीसीआई सुनील शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सीजेआई न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत ने कहा, रोहतक रहा है मेरे लिए प्रेरणा स्थल

कानूनी विचारधारा को सुदृढ़ करने में बार एसोसिएशन का है योगदान

पंकज

चंडीगढ़ देश के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत ने कहा कि रोहतक उनका प्रेरणा स्थल रहा है। रोहतक बार एसोसिएशन का देश में कानूनी विचारधारा को सुदृढ़ करने में योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि बार व बैंच आमजन के न्याय प्रणाली में विश्वास को बहाल रखें। उन्होंने बताया कि भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए सरकार व बार इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स स्थापित करने बारे भी विचार करें। देश के सर्वोच्च न्यायालय के नए भवन का तीन चरणों में निर्माण किया जा रहा है, जिसके उपरांत आगामी 50 वर्षों तक यह न्यायालय परिसर पर्याप्त होगा। न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत आज रोहतक के न्यायिक परिसर में जिला बार एसोसिएशन द्वारा देश के मुख्य न्यायाधीश के सम्मान में आयोजित सम्मान समारोह समारोह में बतौर मुख्यातिथि न्यायिक अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत ने कहा कि भारतीय प्राचीन परम्परा अतिथि देवो भव- के अनुसार अतिथि को ईश्वर के रूप में माना जाता है। उन्होंने कहा कि उनके अंदर का वकील हमेशा जीवित रहा है, चाहे वे

किसी भी पद पर आसीन रहे हो। रोहतक बार के साथ उनका भावनात्मक रूप से गहरा नाता है तथा वे इस दौरा कार्यक्रम को लेकर उत्सुक थे। रोहतक बार हमेशा उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही है। माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत ने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में दो महत्वपूर्ण क्षेत्र कर्म क्षेत्र व प्रेरणा क्षेत्र होते है। रोहतक से उन्होंने कानून की पढ़ाई की तथा यहां से प्रेरणा प्राप्त की। उन्होंने कहा कि रोहतक बार से उन्होंने अनुशासन एवं गहन विषयों की जानकारी हासिल की तथा बार में उन्हें हमेशा अपार प्यार व स्नेह दिया है। उनके शपथ ग्रहण समारोह का रोहतक बार ने लाइव टेलीकास्ट किया तथा उनके जन्मदिन के अवसर पर रोहतक बार में केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया गया। वे रोहतक बार से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए है। उन्होंने कहा कि बार में भारतीय न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने में भी योगदान दिया है। न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के नए भवन का तीन चरणों में निर्माण जारी है। इस नए भवन में 34 नए कोर्ट रूम बनाये जा रहे है, जो आगामी 50 वर्ष की व्यवस्था के लिए पर्याप्त होंगे। गत दिनों उन्होंने उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्पलेक्स का उद्घाटन करने का अवसर मिला, जहां पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह कॉम्पलेक्स तैयार किया गया है। उन्होंने सरकार व जिला बार एसोसिएशन से कहा कि वे भी ऐसे कॉम्पलेक्स के बारे में विचार करें। उन्होंने बार एसोसिएशन की ओर से रखी मांग के संदर्भ में कहा कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन रोहतक बार की समस्या का कानून मर्यादा का पालन करते हुए समाधान करवाये। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू ने बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मानित किया।

देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत का पगड़ी पहनाकर किया गया मान–सम्मान

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया ने देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत को मान–सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को स्मृति चिन्ह भेंट किया। जिला एवं सत्र डिवीजन के प्रशासनिक न्यायाधीश विकास सूरी ने मुख्य न्यायाधीश को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। उपायुक्त सचिन गुप्ता देश के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत को जिला प्रशासन की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया। वकीलों द्वारा मुख्य न्यायाधीश को भेंट किये गए उनके चित्र पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने हस्ताक्षर किए, जिसे बार रूम में रखा जायेगा।

जिला बार एसोसिएशन रोहतक द्वारा पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। जिला बार एसोसिएशन की ओर से हरियाणा के सहकारिता, निर्वाचन, कारागार, पर्यटन एवं विरासत मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा को स्मृतिचिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। बार एसोसिएशन द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी तथा रोहतक जिला व सत्र डिवीजन के प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति विकास सूरी को भी स्मृतिचिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

सम्मान समारोह में यह रहे उपस्थित

इस अवसर पर पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा सम्मान समारोह के विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति शील नागू, बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी तथा रोहतक जिला व सत्र डिविजन के प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति विकास सूरी, हरियाणा के सहकारिता, निर्वाचन, कारागार, पर्यटन एवं विरासत मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय वशिष्ठ, न्यायमूर्ति राजेश भारद्वाज, न्यायमूर्ति हरकेश, न्यायमूर्ति कुलदीप तिवारी, न्यायमूर्ति नमित कुमार, न्यायमूर्ति दीपक मनचंदा, न्यायमूर्ति नीरजा कुलवंत कलसन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया, उपायुक्त सचिन गुप्ता, नगर निगम आयुक्त डॉ. आनंद शर्मा, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भौरिया, पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के सदस्य व पूर्व प्रधान डॉ. विजेंद्र अहलावत सहित अन्य न्यायाधीश व न्यायिक अधिकारी व अधिवक्ता गण मौजूद रहे।

पंजाब सरकार द्वारा सतलुज और स्वां दरिया के क्षेत्रों के लिए 52 करोड़ रुपये की व्यापक बाढ़ सुरक्षा योजना को मंजूरी-हरजोत सिंह बैंस

श्री आनंदपुर साहिब हलके के संवेदनशील गांवों की सुरक्षा के लिए 11,000 फुट से अधिक लंबे डंगों का किया जाएगा निर्माण

डा. सुभाष चंद्र शर्मा

चंडीगढ़, पंजाब के शिक्षा एवं सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने आज श्री आनंदपुर साहिब हलके में सतलुज और स्वां दरियाओं के किनारे बसे गांवों के लिए 52 करोड़ रुपये की व्यापक बाढ़ सुरक्षा योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने मानसून सीजन के दौरान बाढ़ की मार झेलते आ रहे कई प्रभावित क्षेत्रों के लिए स्थायी समाधान सुनिश्चित किए हैं। इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने कहा, 卐श्री आनंदपुर साहिब हलके में सतलुज और स्वां के किनारे रहने वाले निवासियों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए पंजाब सरकार ने 52 करोड़ रुपये की व्यापक बाढ़ सुरक्षा योजना की घोषणा की है ताकि मानसून के दौरान बाढ़ की मार झेलते आ रहे कई संवेदनशील गांवों को स्थायी रूप से सुरक्षित बनाया जा सके।卐 स. हरजोत सिंह बैंस ने कहा, 卐मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने इस क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा बुनियादी ढांचे से संबंधित व्यापक परियोजनाओं में तेजी लाई है। 52 करोड़ रुपये के कार्यों के लिए पहले ही टेंडर जारी किए जा चुके हैं और कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के निर्माण में पंद्रह दिनों के भीतर और तेजी लाई जाएगी। इसके अलावा, 30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजनाएं विचाराधीन हैं।इस पहल के महत्व को उजागर करते हुए स. बैंस ने कहा, 卐हमारे लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। पिछले वर्ष आई भीषण बाढ़ ने हमें सबक सिखाया है। हम ठोस और दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं।प्रमुख परियोजनाओं के बारे में जानकारी साझा करते हुए स. बैंस ने कहा, 卐गांव दसगराईं और महैन में डंगा निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। गांव हरसा बेला, जहां पिछले वर्ष 4.5 करोड़ रुपये के बाढ़ सुरक्षा कार्य किए गए थे, को उन्नत डिजाइन वाले 2,200 फुट लंबे डंगे के निर्माण हेतु 9 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।卐 मंत्री ने कहा, 卐गांव महिंदली कलां को 8.75 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 1,800 फुट लंबा नया डंगा मिलेगा, जहां मैंने पिछले वर्ष बचाव कार्यों के दौरान व्यक्तिगत रूप से सेवा की थी। गांव अगमपुर में गांव और पुल की सुरक्षा के लिए 12 करोड़ रुपये की लागत से 3,200 फुट लंबा विशाल डंगा (रेवेटमेंट) बनाया जाएगा।उन्होंने कहा, 卐गांव बुर्ज में 7 करोड़ रुपये की लागत से 700 फुट लंबा रेवेटमेंट बनाया जाएगा। इसी प्रकार, गांव अजोली में 3.5 करोड़ रुपये की लागत से 700 फुट लंबा रेवेटमेंट बनाया जाएगा, जबकि गांव लोधीपुर को 9 करोड़ रुपये की लागत से 2,000 फुट लंबे रेवेटमेंट से सुरक्षित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि 卐इन प्रमुख स्थानों के अलावा भलाण, त्रिवेणी मंदिर, नानगरां सहित अन्य गांवों के लिए भी बाढ़ सुरक्षा कार्य प्रगति पर हैं या मंजूर किए जा चुके हैं। स. बैंस ने कहा, 卐इन परियोजनाओं में 11,000 फुट लंबे डंगों का निर्माण शामिल है। हमने पहले ही जमीनी कार्य पूरा कर लिया है और स्थानीय मांगों के आधार पर इसके विस्तार के लिए प्रतिबद्ध हैं।मानसून की शुरुआत से पहले क्षेत्रवासियों को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा, 卐मैं व्यक्तिगत रूप से इन परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी कर रहा हूं और इस मानसून की शुरुआत से पहले बाढ़ सुरक्षा कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हूं।

पंजाब के कराधान विभाग द्वारा 9 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले और आंतरिक अनुशासनहीनता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई- हरपाल सिंह चीमा

लुधियाना का कारोबारी 9 करोड़ रुपये के घोटाले में गिरफ्तार- हरपाल सिंह चीमा

पंकज

चंडीगढ़, दो महत्वपूर्ण मोर्चों पर निर्णायक कार्रवाई का ऐलान करते हुए पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब सरकार की वित्तीय ईमानदारी और प्रशासनिक जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने बताया कि लुधियाना के एक कारोबारी को 9 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले में गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आबकारी एवं कर इंस्पेक्टर को लंबे समय से बिना सूचना के गैर–हाजिर रहने के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। यहां जारी प्रेस बयान के द्वारा वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि स्टेट इंटेलिजेंस एंड प्रिवेंटिव यूनिट (सीआईपीयू), लुधियाना द्वारा की गई एक बड़ी कार्रवाई के दौरान कर विभाग ने मेसर्स एम.ए.ए. स्टील, लुधियाना के मालिक रोहित गुप्ता को गिरफ्तार किया है। केस का विवरण देते हुए उन्होंने कहा, 卐कराधान विभाग ने एक बड़े जीएसटी घोटाले का पर्दाफाश किया है, जहां मेसर्स एम.ए.ए. स्टील द्वारा बिना किसी वास्तविक सप्लाई के एच.आर./सी.आर. कॉइल्स और स्ट्रिप्स के जाली इनवॉइस जारी किए जा रहे थे। इस धोखाधड़ी वाले नेटवर्क के द्वारा 9 करोड़ रुपये से अधिक का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) विभिन्न लाभार्थियों को दिया गया, जिससे सरकारी खजाने को सीधा और बड़ा नुकसान हुआ। छापेमारी के दौरान विभाग की टीमों ने मौके पर मौजूद स्टॉक और फर्म के आधिकारिक बुक रिकॉर्ड में भी बड़ा अंतर पाया है। वित्त मंत्री ने आगे बताया कि इस मामले में जांच का दायरा और बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा, 卐हम साइकिल पार्ट्स और स्पेयर पार्ट्स के कई निर्माताओं की जांच कर रहे हैं, जिनके इस घोटाले में शामिल होने का संदेह है। ये इकाइयां गलत तरीके से एक्सपोर्ट रिफंड या इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के माध्यम से लाभ लेने के लिए जांच के घेरे में हैं। हमारी सरकार कर चोरी के खिलाफ सख्ती से लड़ने, सरकारी राजस्व की रक्षा करने और पंजाब के हर ईमानदार करदाता के लिए बराबर के अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दौरान आंतरिक प्रशासनिक अनुशासन के बारे में बात करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि पंजाब सरकार ने एक आबकारी एवं कर इंस्पेक्टर को लंबे समय से गैर–हाजिर रहने के कारण पंजाब सिविल सर्विसेज़ (सज़ा और अपील) नियम, 1970 के तहत तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। अनुशासन के प्रति पंजाब सरकार के सख्त रुख पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, 卐भगवंत मान सरकार इस बात के लिए दृढ़ है कि किसी भी कीमत पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम पहले भी ऐसी अनुशासनहीनता के कारण चार कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर चुके हैं और एक अन्य आबकारी एवं कर इंस्पेक्टर तथा एक क्लर्क के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी है। आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की जवाबदेही, कार्यकुशलता और अनुशासनिक व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ये कार्रवाइयां राज्य सरकार के संकल्प को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा, 卐हम कर चोरी और सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली किसी भी चूक के खिलाफ जीरो–टॉलरेंस नीति जारी रखेंगे।

हथियार तस्करी वाले माड्यूल से सम्बन्धित दो व्यक्ति 5 अति-आधुनिक पिस्तौलों समेत अमृतसर से गिरफ़्तार

गिरफ़्तार आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के द्वारा पाकिस्तान- आधारित तस्करों के संपर्क में थे–डीजीपी गौरव यादव

रमन कुमार

चंडीगढ़/ अमृतसर, मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा– निर्देशों पर पंजाब को गैंगस्टर मुक्त बनाने के लिए शुरु की गई %गैंगस्टरा ते वार %मुहिम में एक बड़ी सफलता हासिल करते अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने वाले माड्यूल का पर्दाफाश करके पांच आधुनिक पिस्तौलों समेत दो आरोपियों को गिरफ़्तार किया है। यह जानकारी आज यहां डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

गिरफ़्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान रोहित अरोड़ा (25), जो कि अमृतसर के गिलवाली गेट का रहने वाला है और अमृतसर के गांव मीराकोट कलां निवासी हरप्रीत सिंह उर्फ हैपी (24) के तौर पर हुई है। बरामद किए गए पिस्तौलों में तीन 9 एमएम गलौक और दो. 30 बोर पिस्तौल शामिल है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्राथमिक जांच से यह सामने आया है कि उक्त आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के द्वारा पाकिस्तान आधारित तस्करों के संपर्क में थे। उन्होंने कहा कि हथियारों की खेप ड्रोन के द्वारा भेजी जा रही थी और मुलजिम अपने हैंडलरों के निर्देशों पर इनको आगे स्पलाई करते थे। डीजीपी ने कहा कि हथियारों के इस ग़ैर– कानूनी नैटवर्क में अगले– पिछले संबंधों का पता लगाने के लिए आगे वाली जांच जारी है। पुलिस कमिश्नर (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि भरोसेयोग सूत्रों से मिली गुप्त जानकारी के आधार पर कार्यवाही करते पुलिस टीमों ने एक योजनाबद्ध आप्रेशन चलाया और आरोपी रोहित अरोड़ा, जो कि गैंगस्टर सोनू कंगला का नज़दीकी साथी है, को गिरफ़्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि तलाशी दौरान मुलजिम के कब्ज़े में से तीन पिस्तौल– जिस में एक गलौक पिस्तौल और दो . 30 बोर पिस्तौल शामिल हैं, बरामद किए गए। पुलिस कमिशनर ने बताया कि पूछताछ दौरान आरोपी रोहित अरोड़ा की तरफ से किए गए खुलासों के आधार पर एक ओर आरोपी हरप्रीत सिंह उर्फ हैपी को भी दो गलौक पिस्तौलों समेत गिरफ़्तार कर लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि दोनों आरोपी आदतन अपराधी है जिन पर बंदूक की नोक पर लूट– छीन, जेल एक्ट, हथियार एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पहले भी कई केस दर्ज है और उक्त दोनों आसानी के साथ पैसा बनाने (इजी मनी) के इरादे के साथ नशों– हथियारों की तस्करी करते रहे है। इस सम्बन्ध में अमृतसर के थाना गेट हकीमा में हथियार एक्ट की धाराओ 25, 6 ,7 और 8 के अंतर्गत एफआईआर नंबर 33 तारीख़ 06– 02– 2026 दर्ज है।

आरटीओ ने चलाया रात में विशेष जांच अभियान

नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यावसायिक वाहनों पर की सख्त कार्रवाई

एस. के. सक्सैना

होशियारपुर, डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर के निर्देशों के मद्देनज़र आरटीओ अमनदीप कौर की ओर से जिले में रात के समय विशेष जांच अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़कों पर चल रहे व्यावसायिक वाहनों की जांच कर यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना तथा सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाना था। उन्होंने बताया कि सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल की ओर से भी इस संबंधी निर्देश दिए गए थे। आरटीओ ने बताया कि इस विशेष अभियान के तहत संयुक्त टीमों ने विभिन्न प्रमुख मार्गों, चौक–चौराहों एवं संवेदनशील स्थानों पर नाकाबंदी कर वाहनों की गहन जांच की। जांच के दौरान ओवरलोडिंग, बिना वैध दस्तावेज, प्रदूषण मानकों का उल्लंघन, फिटनेस प्रमाण पत्र की कमी तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कई व्यावसायिक वाहन पकड़े गए। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले अनेक वाहनों के चालान काटे गए, जबकि गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर कुछ ओवरलोडेड वाहनों को मौके पर ही जब्त (इंपाउंड) कर लिया गया। अमनदीप कौर ने बताया कि वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए भविष्य में नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत भी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के विशेष जांच अभियान आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और आम

जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण रखें, ओवरलोडिंग से बचें तथा यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करें, जिससे सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था कायम रखी जा सके।

'सी.एम. दी योगशाला' अभियान के तहत जिले में 349 योग कक्षाएं संचालित - डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन

मनदीप कौर

होशियारपुर, डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार के अभियान 'सी.एम. दी योगशाला' के अंतर्गत जिले भर में निःशुल्क योग कक्षाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन को योग के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 349 योग कक्षाएं नियमित रूप से सुबह व शाम के समय आयोजित की जा रही हैं। इन कक्षाओं में बड़ी संख्या में लोग उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के लाभ प्राप्त कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है, बल्कि मानसिक तनाव को दूर करने और जीवनशैली संबंधी बीमारियों से बचाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे नियमित रूप से योग अभ्यास अपनाएं और स्वस्थ जीवन की दिशा में कदम बढ़ाएं। अभियान के सुचारु एवं प्रभावी संचालन के लिए जिला कोऑर्डिनेटर किरण बाला द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में उपयुक्त स्थान उपलब्ध हो और कम से कम 25 लोगों का समूह तैयार हो, वहां भी नई योग कक्षाएं आरंभ करवाई जाएंगी, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अभियान का लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि योग कक्षाओं का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्ति टोल फ्री नंबर 7669400500 / 7888840161 पर संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन पंजीकरण के लिए संबंधित पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।

पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध; वन विभाग के कर्मचारी सरकार का अभिन्न अंग-लाल चंद कटारूचक

मंत्री ने विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठकों की अध्यक्षता की

एस. के. सक्सैना

चंडीगढ़, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और वन विभाग के कर्मचारी सरकार का अभिन्न अंग हैं। यह विचार आज वन एवं वन्यजीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक ने वन कॉम्प्लेक्स में फॉरेस्ट रेंजर्स एंड डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर्स एसोसिएशन, पंजाब स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बठिंडा के सेवानिवृत्त कर्मचारी यूनियन तथा डेमोक्रेटिक जंगलात मुलाजम यूनियन पंजाब के साथ आयोजित बैठकों के दौरान व्यक्त किए। मंत्री ने वन रेंजर्स को बताया कि वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत विभाग के पुनर्गठन प्रस्ताव के तहत पंजाब फॉरेस्ट सर्विस (ई.ए.सी.एफ.) के 44 पदों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि पुनर्गठन प्रस्ताव में मुकदमेबाजी के मामलों से निपटने के लिए कानून अधिकारी के 2 पद और कानूनी सहायकों के 6 पद भी शामिल किए गए हैं। पी.एफ.एस. कैडर के पदों पर सीधी भर्ती की मांग के संबंध में मंत्री ने कहा कि वन रेंजर्स के संबंध में नियमों को अधिसूचित करने के बाद इस मामले पर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाएगा। पंजाब स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सेवानिवृत्त कर्मचारी यूनियन के साथ बातचीत करते हुए मंत्री ने यूनियन द्वारा उठाए गए पेंशन संबंधी मुद्दे के संदर्भ में कहा कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो इस मुद्दे पर विचार करके रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा मंत्री ने डेमोक्रेटिक जंगलात मुलाजम यूनियन पंजाब के साथ भी मुलाकात की और समय–समय पर विभाग में कार्यरत कच्चे तथा अनपढ़ कर्मचारियों (519 याचिकाकर्ता/गैर–याचिकाकर्ता) की सेवाओं को नियमित करने सहित उनकी विभिन्न मांगों को ध्यान से सुना। इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा अतिरिक्त प्रमुख मुख्य वनपाल (ए.पी.सी.सी.एफ.) सौरभ गुप्ता और मुख्य वन्यजीव वार्डन बसंत राज कुमार भी उपस्थित थे।

कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत ने सुनी हलका वासियों की शिकायतें

कहा, जनसमस्याओं का समाधान है प्राथमिकता

डा. सुभाष चंद्र शर्मा

होशियारपुर, कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने आज अपने कार्यालय में हलके के विभिन्न गांवों व शहरी क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके त्वरित व प्रभावी समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी व्यक्तिगत व सामूहिक समस्याएं लेकर पहुंचे, जिनमें राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल, सड़क, सीवरेज तथा सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी शिकायतों का निपटारा तय समय सीमा के भीतर किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध करवाना है, ताकि लोगों को दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें। कैबिनेट मंत्री ने कई मामलों का मौके पर ही निपटारा करवाते हुए शेष मामलों को संबंधित विभागों को शीघ्र कार्रवाई के लिए भेजा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक शिकायत की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें और शिकायतकर्ता को समाधान की जानकारी भी उपलब्ध कराएं। डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि जनता से सीधा संवाद कायम रखना उनकी प्राथमिकता है, ताकि जमीनी स्तर पर मौजूद समस्याओं को समझकर प्रभावी समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इसी प्रकार नियमित जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे हलके के सर्वांगीण विकास को और गति मिल सके। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

सुरक्षा सेवा पोर्टल पर ओटीपी जनरेशन से जुड़ी दिक्कतों को लेकर सरकार के निर्देश

विभाग सुनिश्चित करें अद्यतन और सटीक कर्मचारी डेटा

मनदीप कौर

चंडीगढ़, –हरियाणा सरकार ने सुरक्षा सेवा पोर्टल पर ओटीपी जनरेशन और कर्मचारी डेटा से जुड़ी समस्याओं के तत्काल और समयबद्ध समाधान के लिए निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों तथा उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पात्र अनुबंध कर्मचारियों का अद्यतन और सटीक डेटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम तथा खजाना एवं लेखा विभाग के डेटाबेस में सुनिश्चित करें, ताकि पात्र कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके। गौरतलब है कि सरकार ने इससे पहले 30 जनवरी को भी विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए थे, लेकिन अब भी कई विभागों और अनुबंध कर्मचारियों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि पात्रता मानदंडों को पूरा करने तथा 15 अगस्त, 2024 तक पांच वर्ष की सेवा पूरी होने के बावजूद ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा है। जांच में पाया गया कि ओटीपी जनरेशन में बाधा के प्रमुख कारणों में गलत या बदला हुआ मोबाइल नंबर, फैमिली आईडी में त्रुटि तथा वेतन या मानदेय का संविदा मद के बजाय अन्य मद से भुगतान शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष या आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) को औपचारिक प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य होगा। इस प्रमाण पत्र में यह पुष्टि करनी होगी कि संबंधित व्यक्ति वास्तविक अनुबंध कर्मचारी है, उसकी पूरी सेवा का विवरण उपलब्ध है, उसकी नियुक्ति अनुबंध आधार पर हुई है तथा भविष्य में वेतन का भुगतान उचित संविदा मद से सुनिश्चित किया जाएगा। बिना सत्यापन प्रमाण पत्र के किसी भी आवेदन पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम और खजाना एवं लेखा विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रमाणित सूचना प्राप्त होने के बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम और खजाना एवं लेखा विभाग आवश्यक कार्रवाई करते हुए सत्यापित डेटा हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन को भेजेंगे, ताकि ओटीपी प्रक्रिया सक्षम हो सके और पोर्टल का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, जिन मामलों में विभाग, जिला कार्यालय, पद या डीडीओ के नाम सुरक्षा सेवा पोर्टल के ड्रॉप–डाउन मेनू में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, उन्हें तत्काल संबंधित प्राधिकरण के संज्ञान में लाकर सुधार कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने दोहराया है कि पार्ट–1 और पार्ट–2 कर्मचारियों के डेटा के प्रबंधन की जिम्मेदारी क्रमशः हरियाणा कौशल रोजगार निगम और kha-jana एवं लेखा विभाग की है। खजाना एवं लेखा विभाग संबंधित डीडीओ से सत्यापित पार्ट–2 डेटा उपलब्ध कराएगा, जबकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम रीयल टाइम सटीक डेटा साझा करेगा, जिससे सुरक्षा सेवा पोर्टल का निर्बाध और सुरक्षित संचालन संभव हो सके।

शहरी क्षेत्रों में स्कूल खोलने हेतू किया जाएगा सर्वे- मुख्यमंत्री

ड्रॉप आउट खत्म कर स्कूली बच्चों को मुख्यधारा में लाया जाए

पंकज

चण्डीगढ, – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में बढती हुई आबादी व क्षेत्र के मध्येनजर बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाने के लिए स्कूल खोलने हेतू सर्वे किया जाए ताकि शहरों में बच्चों को लम्बी दूरी तय करके स्कूल न जाना पड़े। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी बुधवार को राज्य स्तरीय दिशा कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार, सांसद धर्मबीर सिंह, नवीन जिन्दल सहित कई विधायक भी मौजूद रहे। बैठक से सभी जिला के अधिकारी भी ऑनलाईन जुडे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा गत वर्ष स्कूल छोड़ चुके 34 हजार बच्चों में से 18796 बच्चों को 6 माह का प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा उनमें से 15386 बच्चों को मुख्यधारा में लाया गया। इसके अलावा सैक्टर 37 फरीदाबाद में स्कूल भवन का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए हर जिले में मॉडल संस्कृति स्कूल खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर घर ग्रहणी योजना का लाभ पात्र महिलाओं तक पहुंचाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाए। इसके अलावा विशेषकर ढाणियों में रहने वाले नागरिकों के लिए बिजली सुलभ करवाने के लिए लोगों को सोलर सब्सिडी स्कीमों के प्रति जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को टीबी मुक्त और ऐनीमिया मुक्त करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान में राज्य ने 98 प्रतिशत कवर किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में नेच्यूरोपेथी सुविधाएं बढाई जाए ताकि नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिले। जनऔषधी केन्द्र खोलने पर बल दिया जाए ताकि नागरिकों को उचित मूल्य पर दवाईयां सुलभ हो सके

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुए श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में 98726 मकान बनाने के लक्ष्य अनुसार 652 करोड़ रुपए की राशि से 76275 मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं जिनमें से 41491 पूरे हो चुके हैं तथा शेष निर्माणाधीन है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना में 67649 मकान बनाए जाएगें। इसमें से 703 करोड़ रुपए की लागत से 33690 मकान बनाए जा चुके है। उन्होंने कहा कि डा. बी आर अम्बेडकर आवास योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के लिए अनुसूचित जाति के परिवारों की आवेदन प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए ताकि पात्र लोगों को अगले माह राशि मुहैया करवाई जा सके। इसके अलावा युवाओं के लिए अम्बाला में स्टेट सैंट्रल लाईब्रेरी एवं नारनौल में जिला लाईब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। जल शक्ति अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जलभराव वाले क्षेत्रों में वाटर बॉडी बनाने के लिए योजना बनाई जाए ताकि आवश्यकता अनुसार जल का उपयोग किया जा सके। इसके लिए ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव मांगे जाए। उन्होंने कहा कि हिसार ड्रेन व भिवानी ड्रेन को गहरा कर विस्तारीकरण किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। अमृत योजना–2 की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत 27 जल एवं 9 सिवरेज परियोजनाएं चल रही हैं जिन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा लगभग 59 बड़े गांवों में महाग्राम योजना के तहत सिवरेज तथा नई नगरपालिकाओं में भी सिवरेज एवं पेयजल योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 66 हजार शौचालयों का निर्माण किया गया और साथ ही शहरों एवं गांवों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल विभाग द्वारा 257 खेल स्टेडियम के नवीनीकरण पर 314 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1025 व्यायामशालाएं एवं इंडोर जिम बनाए गए है। व्यायामशालाओं में ट्रैक निर्माण को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सैर के लिए बेहतर स्थान सुलभ हो सके। बैठक में अन्य विभागों की भी विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरूण गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. साकेत कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजा शेखर वुंदरू, विनित गर्ग, जी अनुपमा, अनुराग अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

राज्य सरकार मिलावटी एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी -आरती सिंह राव

रमन कुमार

मिलावटी दूध उत्पादों पर हरियाणा सरकार की बड़ी कार्रवाई

चंडीगढ़, – हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार मिलावटी एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई करेगी। मिलावट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है और जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ छापामारी करने के निर्देश दिए गए हैं , यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हरियाणा के आयुक्त डॉ मनोज कुमार ने बताया कि प्रदेश में लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन (ऱ्ब्रष्ठ) ने दूध और दूध से बने उत्पादों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक राज्य के विभिन्न जिलों में पनीर, देसी घी, दूध एवं अन्य दुग्ध उत्पादों के सैंपल लेकर जांच के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं में भेजे गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर कई नमूने असुरक्षित, अवमानक तथा गलत ब्रांडिंग वाले पाए गए। इसके बाद विभाग ने संबंधित खाद्य कारोबार संचालकों (ऱ्ब्रह्नह्य) के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। डॉ मनोज कुमार ने बताया कि पलवल, हिसार, नूंह, महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी और पानीपत सहित कई जिलों के विक्रेताओं की जांच की गई। कई स्थानों पर पनीर और देसी घी के नमूने फेल पाए गए, जिनकी बिक्री पर रोक लगाई गई है। कुछ मामलों में दुकानों को सील करने और एफआईआर दर्ज करने जैसी कार्रवाई भी की गई है, जबकि अन्य मामलों में कानूनी प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि पलवल में श्री सैकुल खान पुत्र श्री जंगी के मिल्क प्लांट में पनीर की रिपोर्ट असुरक्षित एवं अवमानक पाई गई। इसी प्रकार , हिसार जिला में राधिका इंटरप्राइजिज पर छापा मरकर देसी घी के सैंपल लिए गए जो कि असुरक्षित , अवमानक और बिक्री के लिए प्रतिबंधित पाए गए। इस मामले में श्री सुरेंद्र कुमार पुत्र श्री रामचंद तथा श्री अमित सचदेवा पुत्र श्री सुरेंद्र कुमार की दुकान सील कर दी गई और एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसी जिला में श्री शिव कुमार पुत्र श्री ऋषिकेश , दिनेश सिंगल पुत्र शेर सिंगल तथा श्री रविंद्र पुत्र श्री कृष्ण के इंटरप्राइजिज पर देसी घी के सैंपल लिए गए जो असुरक्षित , अवमानक और बिक्री के लिए प्रतिबंधित पाए गए। नूह जिला में श्री जकारिया खान पुत्र सहीद अहमद का देसी घी का ब्रांड गलत पाया गया। इसी जिला में मोहम्मद सोहिल पुत्र ताहिर तथा ताहिर पुत्र असलम के संस्थानपर पनीर की जाँच की गई जिसमें असुरक्षित , अवमानक और बिक्री के लिए प्रतिबंधित पाया गया है।

हरियाणा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 2.39 करोड़ रुपये के चिकित्सा उपकरणों की खरीद को दी मंजूरी

डा. सुभाष चंद्र शर्मा

चंडीगढ़, हरियाणा सरकार ने 2.39 करोड़ रुपये के सूक्ष्म चिकित्सा उपकरण खरीदने को मंजूरी दे दी है, जिसमें 25 स्लिट लैंप, 140 रेडिएंट वार्मर, 60 एलईडी फोटोथेरेपी यूनिट और 1,575 प्लास्टिक मोल्डेड पैलेट शामिल हैं। इससे राज्यभर में मरीज़ों की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी और हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर मज़बूत होगा। ये उपकरण नागरिक अस्पतालों तथा नवजात शिशु देखभाल इकाइयों (नियोनेटल केयर यूनिट) में सप्लाई किए जाएंगे, जिससे सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निदान, उपचार और भण्डारण की सुविधा अधिक होगी। यह निर्णय हरियाणा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा की अध्यक्षता में विशेष स्थायी क्रय समिति (हायर) की बैठक में लिया गया। यह खरीद दो वर्ष के रेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत की जाएगी, जिसमें उपकरणों के निर्बाध संचालन हेतु काम करने के लिए मेंटेनेंस सपोर्ट भी शामिल है। डॉ. मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 74 लाख रुपये की लागत 25 स्लिट लैंप खरीदे जाएंगे, जो सिविल अस्पतालों के नेत्र रोग विभाग में स्थापित किए जाएंगे ताकि इन उपकरणों के माध्यम से नेत्र संबंधी रोगों की समय पर पहचान और उपचार सुनिश्चित किया जा सके। नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए लगभग 82 लाख रुपये की लागत से 140 रेडिएंट वार्मर खरीदे जाएंगे, जो जन्म के तुरंत बाद नवजात बच्चों के शरीर का सही तापमान बनाए रखने में सहायक होंगे तथा जटिलताओं के जोखिम को कम करेंगे। इसके अलावा, 32 लाख रुपये की कीमत वाली 60 ऐलईडी फोटोथेरेपी यूनिट्स का इस्तेमाल नवजात पीलिया (नियोनेटल जॉन्डिस) के इलाज के लिए किया जाएगा, जो नवजात बच्चों में एक सामान्य, लेकिन गंभीर बीमारी हो सकती है। लॉजिस्टिक्स एवं भण्डारण क्षमता को बेहतर बनाने के लिए, 51 लाख रुपये की कीमत वाले 1,575 प्लास्टिक मोल्डेड पैलेट एचएमएससीएल वेयरहाउस को उपलब्ध करवाए जाएंगे। इससे दवाओं एवं चिकित्सा सामग्री के सुरक्षित भण्डारण तथा इन्वेंट्री प्रबंधन में सुधार होगा। डॉ. मिश्रा ने कहा कि यह पहल हरियाणा के सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे मरीजों, विशेषरूप से नवजात बच्चों और नेत्र रोगियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का सीधा लाभ होगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट खर्च और जरूरी विभागीय स्कीमों की प्रगति की करी समीक्षा

मुख्यमंत्री ने हरियाणा में पीएम कुसुम और रूफटॉप सोलर स्कीमों को समय पर लागू करने के दिए निर्देश

एस. के. सक्सैना

चंडीगढ़, 10 फरवरी – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को अलग–अलग विभागों के बजट खर्च और जरूरी विभागीय स्कीमों की प्रगति को लेकर एक हाई–लेवल रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। मीटिंग में संबंधित विभागों के वरिष्ठ प्रषासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए, अधिकारियों को राज्य में खेती के पंपों को सोलर आधारित करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना को समय पर लागू किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सोलर पंपों से पैदा होने वाली सरप्लस बिजली को सरकारी ग्रिड में वापस भेजा जाना चाहिए, ताकि इसका सदुपयोग हो सके। उन्होंने अधिकारियों को राज्य की सभी सरकारी इमारतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने में तेजी लाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि बस स्टैंड, हैफेड गोदाम और दूसरे सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर के माध्यम से नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने पर विषेष बल दिया है।

मीटिंग के दौरान, अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 5,000 सरकारी इमारतों का सर्वे पूरा कर लिया गया है और रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सभी जिलों के उपायुक्त इस स्कीम को लागू करने में तेजी लाएंगें और तत्परता से इसकी निगरानी करेंगे।

परिवहन विभाग की स्कीमों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खराब हालत वाले बस स्टैंड की पहचान करने और उनकी मरम्मत एवं रखरखाव करने के निर्देश दिये। कनीना, बरवाला, टोहाना और निग्धू में बस स्टैंड कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं, जबकि बादली, नीलोखेड़ी, बहल और दूसरे स्थानों पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और इको–फ्रेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने तथा कार्बन ईमिशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने पर भी बल दिया।

उद्योग विभाग की स्कीमों की समीक्षा करते हुए, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एमएमएमई के तहत छोटे उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन देने के निर्देश दिये। उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाने की जरूरत पर बल दिया जो खासकर महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दें, ताकि इनक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया जा सके।

पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खैर के पेड़ों की गैर–कानूनी कटाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये। उन्होंने जंगलों की कटाई को रोकने, हरित क्षेत्र बढ़ाने और राज्य भर में पेड़ों की सही मार्किंग करने के लिए तत्परता से कदम उठाने के निर्देश दिये। उन्होंने अरावली क्षेत्र में कंजर्वेशन की जरूरत पर भी बल दिया। विदेष सहयोग विभाग की समीक्षा के दौरान, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एनआरआई डायस्पोरा के साथ सीधा मजबूत जुड़ाव बनाने और जहाँ भी जरूरत हो, मदद देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विदेश में पढ़ने या काम करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को विदेषी भाषा सिखाने के कार्यक्रम भी चलाएं जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के कार्यो की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि किसान हरियाणा की आर्थिक रीढ़ है और किसानों की आय और उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने निर्देश दिये कि और ज्यादा से ज्यादा 'हर हित स्टोर' सीएम पेक्सस खोले जाएं और स्वयं सहायता समूहों को सौंपे जाएं ताकि महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को रोजगार के बेहतर अवसर सुलभ हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में दालों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए और दालों की खेती करने वाले किसानों को बढ़ावा देने के लिए एक विषेष नीति बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हरियाणा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन अनुसार दालों के उत्पादन में 'आत्मनिर्भरता' की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की अपील करते हुए किसानों को ऑर्गेनिक खेती के तरीके अपनाने के लिए सहयोग और बढ़ावा देने के लिए भी विषेष स्कीम बनाने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने अन्य विभागों के बजट खर्च और स्कीमों की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री. श्याम सिंह राणा, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. साकेत कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

पेंशन को लेकर विपक्ष फैला रहा भ्रम, हर गरीब तक सीधा लाभ पहुंचा रही है डबल इंजन सरकार-मुख्यमंत्री

मनदीप कौर

चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पेंशन को लेकर विपक्ष भ्रामक प्रचार कर रहा है। जबकि लाभार्थी का पैसा सीधा उस गरीब आदमी के खाते में जाए इस गारंटी के साथ डबल इंजन सरकार काम कर रही है। मोदी सरकार की गारंटी पर देश की जनता को विश्वास है। मुख्यमंत्री मंगलवार को हरियाणा निवास में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने तो झूठ की दुकान खोली हुई है और लगातार इसके नेता भ्रामक प्रचार करने में लगे है। कांग्रेसी नेता लगातार बयान दे रहे है कि प्रदेश में दो लाख लोगों की पेंशन काट दी गई है। जबकि सच यह है कि बुजुर्गों का सम्मान करना तो हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी बुजुर्गो के हितों की हमेशा बात की है और हमने भी अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है या फिर उनका स्वास्थ्य खराब होता है, तो उनके इलाज की चिंता उनके परिवार को नहीं करनी। बल्कि ईलाज की चिंता मोदी सरकार और हरियाणा सरकार करेगी। इसी के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गो को 5 लाख रुपये तक का ईलाज मुफ्त दिया जा रहा है।

पंजाब में केवल 1500 रुपये पेंशन–मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर पेंशन केवल मात्र 1500 रुपये दी जा रही है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता को वहां की सरकार ने सब्जबाग दिखाए है कि पेंशन 2500 रुपये कर देंगे, लेकिन किया कुछ नहीं। जबकि बीजेपी सरकार ने जो कहा वो किया, और आज देश में सबसे ज्यादा बुजुर्ग सम्मान राशि हरियाणा में दी जा रही है।

विपक्षी उंगली कटवा कर शहीद होना चाहते है–मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस की बात हो या इनेलो की। जब इनकी सरकार थी, तब इन्होंने कुछ नहीं किया। पेंशन में केवल नाम मात्र बढ़ोतरी की गई। पेंशन को लेकर तो इनका हाल ऐसा है कि उंगली कटवाकर खुद को शहीद साबित करने की कोशिश कर रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने कभी इनकम स्लैब नहीं लगाई, लेकिन इस पर भी आमजन को गुमराह किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इनेलो के पांच साल के शासनकाल में वृद्धावस्था पेंशन में केवल 200 रुपये की बढ़ोतरी हुई। इसी प्रकार, कांग्रेस के 10 वर्ष के शासनकाल में केवल 700 रुपये की बढ़ोतरी हुई। जबकि वर्तमान बीजेपी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3200 रुपये मासिक की है। इस प्रकार, सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2200 रुपये की बढ़ोतरी की है। वर्तमान में 20 लाख 31 हजार 367 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा है।

पेंशन काटी नहीं, रोकी गई है- मुख्यमंत्री–हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के 2 लाख लोगों की पेंशन काट दी गई, ऐसा भ्रम फैलाने में विपक्ष जुटा है। जबकि सच्चाई यह है कि जब किसी पेंशन लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो नियमानुसार उसकी पेंशन स्वत: बंद कर दी जाती है। दो लाख मामलों में से लगभग 1 लाख 3 तीन हजार (आधे से भी अधिक) ऐसे लाभार्थी हैं, जिनकी मृत्यु के उपरांत पेंशन बंद की गई है। उन्होंने बताया कि अक्तूबर, 2024 से रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया पोर्टल में किसी तकनीकी समस्या के कारण प्रदेश सरकार को हरियाणा में मृत हुए व्यक्तियों का डाटा नहीं मिला था। यह डाटा नवंबर, 2025 में प्राप्त होने के बाद एकमुश्त में ऐसे मृतकों की पेंशन कटी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 37 हजार ऐसे मामले सामने आए थे, जिनमें वास्तविक आयु 60 वर्ष से कम थी। लोगों ने डाटाबेस में छेड़छाड़ करके पेंशन स्वीकृत करवा ली थी। इन लाभार्थियों की पेंशन स्थगित कर दी गई है। डाटाबेस में छेड़?छाड़ करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। यदि ये लोग अपनी आयु 60 वर्ष से अधिक होने का कोई प्रमाण देंगे, तो इनकी पेंशन पुन: शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा करीब 39 हजार मामलों में स्थानीय समिति एवं सेक्टर समिति द्वारा आय आधारित पात्रता का सत्यापन नहीं किया गया था। ऐसे मामलों में आय का प्रमाण दिया जाएगा, तो तुंरत उसका सत्यापन करवाया जाएगा और प्रमाण सही पाए जाने पर पेंशन बहाल कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन पर आय सीमा प्रदेश की बीजेपी सरकार ने नहीं लगाई। प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन पर पहली बार 10 हजार रुपये वार्षिक आय सीमा 13 अगस्त, 1992 को लगाई गई थी। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय वृद्धावस्था पेंशन भी 100 रुपये मासिक थी। उस समय 6 लाख 50 हजार बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता था। इसके बाद पहली नवंबर, 1999 को इनेलो ने अपने कार्यकाल में वृद्धावस्था पेंशन 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये मासिक की।

पंजाब पुलिस ने पाक- आधारित माड्यूल का पर्दाफाश करके एक ओर आतंकवादी साजिश को किया नाकाम; आईडी और पिस्तौल समेत आरोपी गिरफ्तार

आईईडी का प्रयोग पंजाब और दिल्ली समेत कई राज्यों में योजनाबद्ध हमलों में किया जाना था–डीजीपी गौरव यादव

डा. सुभाष चंद्र शर्मा

चंडीगढ़/ अमृतसर, मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए जारी मुहिम दौरान ख़ुफ़िया जानकारी पर आधारित एक कार्यवाही में स्टेट स्पेशल आपरेशन सैल (एस. एस. ओ. सी.) अमृतसर ने पाकिस्तान की हिमायत वाले एक ओर आतंकवादी माड्यूल का पर्दाफाश करते एक बड़ी आतंकवादी साजिश को नाकाम कर दिया है और इस कार्यवाही में गिरफ़्तार किए गए दोषी से रिमोट कंट्रोल समेत मटैलिक केस में पैक एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) और गोली– सिक्के समेत एक विदेशी पिस्तौल बरामद किया गया है। यह जानकारी आज यहां डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी। गिरफ़्तार किए गए आरोपी की पहचान शुभम कुमार उर्फ शुभम श्रीवास्तव के तौर पर हुई है, जो सीतापुर, उत्तर प्रदेश के गांव सरोसा का रहने वाला है। बताने योग्य है कि यह सफलता पंजाब पुलिस की तरफ से पाकिस्तान आई.एस.आई. की हिमायत वाले आतंकवादी माड्यूल

का पर्दाफाश करने उपरांत इसके साथ सम्बन्धित कारकुन, जिसकी पहचान अमृतसर के राहुल कुमार उर्फ गज्जू के तौर पर हुई है, को आरडीएक्स–आधारित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) समेत गिरफ़्तार किए जाने से एक दिन बाद सामने आई है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्राथमिक जांच अनुसार गिरफ़्तार किया गया मुलजिम ऐनक्रिपटड प्लेटफार्मों के द्वारा पाकिस्तान– आधारित हैंडलर के संपर्क में था। उन्होंने कहा कि आरोपी से बरामद हुई खेप सरहद पार से भेजी गई थी, जिसको उसने शहर के बाहरवार एक निर्धारित स्थान से प्राप्त किया था। डीजीपी ने कहा कि यह आई.ई.डी. पंजाब और दिल्ली समेत कई राज्यों में योजनाबद्ध हमलों में इस्तेमाल किया जाना था। उन्होंने आगे कहा कि समूचे आतंकवादी नैटवर्क का ख़ात्मा करने के लिए आगे वाली जांच जारी है। एआईजी एसएसओसी अमृतसर सुखमिन्दर सिंह मान ने कहा कि पुलिस टीमें को एक ठोस जानकारी मिली थी कि पाकिस्तानी संचालकों द्वारा पंजाब, दिल्ली और देश के अलग– अलग हिस्सों में धमाके और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के इरादे के साथ आईईडी और हथियारों की एक खेप पाकिस्तान से ड्रोन के द्वारा भेजी गई है, जिसको उनके भारत में कारकुनौ ने हासिल किया है। प्राप्त जानकारी पर तेज़ी के साथ कार्यवाही करते विशेष पुलिस टीमों का गठन करके एक स्पैशल आप्रेशन चलाया गया, जिस दौरान शक्की शुभम कुमार उर्फ शुभम श्रीवास्तव को गिरफ़्तार करके अमृतसर जालंधर जीटी रोड पर स्थित दरगाहा नज़दीक खाली पड़ी जगह से आईईडी और पिस्तौल किया गया। एआईजी ने कहा कि जांच मुताबिक गिरफ़्तार किया गया दोषी पूरी तरह कट्टरपंथी है और वह अपने हैंडलर से अच्छे पैसे मिलने के भरोसे के बाद में उत्तर प्रदेश से अमृतसर आया था और उसने अपने हैंडलर के निर्देशों पर शहर के बाहरवार एक निर्धारित स्थान से आईईडी और हथियारों की खेप हासिल की थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच जारी है। इस सम्बन्धित थाना एस. एस.ओ.सी., अमृतसर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2, ग़ैर– कानूनी गतिविधियों (रोकू) एक्ट (यूएपीए) की धारा 18 और 20, विस्फोटक पदार्थ एक्ट की धारा 4 और हथियार एक्ट की धारा 25(1 (डी) के अंतर्गत एफआईआर नं. 09 तारीख़ 10. 02. 2026 दर्ज की गई है।

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने 13 कृषि सब–इंस्पेक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपे

कृषि मंत्री ने नव–नियुक्त ए.एस.आईज़. को बधाई दी

एस. के. सक्सैना

चंडीगढ़, राज्य के कृषि आधारभूत ढांचे और जमीनी स्तर पर सेवाओं के विस्तार को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सरदार गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज यहां अपने कार्यालय में 13 नव–नियुक्त कृषि सब–इंस्पेक्टरों (ए.एस.आई.) को नियुक्ति पत्र सौंपे। नव–नियुक्त ए.एस.आईज़. को सरकार की प्रगतिशील नीतियों और किसानों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने उन्हें बधाई दी और पूर्ण ईमानदारी एवं समर्पण के साथ राज्य के किसानों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने नव–नियुक्त कर्मचारियों से कहा कि आपका आचरण और जिम्मेदारी कृषि क्षेत्र की समृद्धि पर सीधा प्रभाव डालेगी क्योंकि आप आज देश के 'अन्नदाता के प्रति अपनी जिम्मेदारी से जुड़ रहे हैं। कृषि विभाग में कर्मचारी सेवाओं के विस्तार पर सरकार द्वारा दिया जा रहा निरंतर ध्यान विस्तार से बताते हुए सरदार खुड्डियां ने कहा कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार के सत्ता संभालने से अब तक कृषि विभाग में 133 कृषि सब–इंस्पेक्टर (ए.एस.आईज़.) और 200 कृषि विकास अधिकारी (ए.डी.ओज़.) की भर्ती की गई है। उन्होंने कहा कि ये भर्तियां विभाग में नई ऊर्जा का संचार कर रही हैं और किसानों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करने की हमारी क्षमता को और मजबूत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में 63,943 युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर इन भर्तियों से विभिन्न विभागों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरा गया है, जो पंजाब के लोगों को कुशल और पारदर्शी ढंग से सेवाएं प्रदान करने के प्रति राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव अर्शदीप थिंद, निदेशक कृषि गुरजीत सिंह बराड़ और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

'पंजाब सरकार ने साडे बुज़ुर्ग, साड्डा मान के नारे को मजबूत करते हुए वर्ष 2025-26 में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 3,806 करोड़ रुपये जारी किए-डॉ. बलजीत कौर

23.62 लाख से अधिक बुजुर्ग नागरिक सम्मान और सुरक्षा के साथ 1,500 रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं

रमन कुमार

चंडीगढ़, पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के गतिशील नेतृत्व में पंजाब सरकार बुजुर्ग नागरिकों को न केवल समाज का अभिन्न अंग मानती है, बल्कि अपनी जीवंत विरासत और गौरव भी मानती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान जनवरी 2026 तक वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 3,806 करोड़ रुपये से अधिक जारी करके 'साड्डे बुजुर्ग, साड्डा मान' के नारे को व्यावहारिक रूप दिया है। मंत्री ने कहा, 卐पूरे राज्य में 23.62 लाख से अधिक पात्र बुजुर्ग लाभार्थियों को वृद्धावस्था

पेंशन योजना के तहत नियमित रूप से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। प्रत्येक पात्र बुजुर्ग नागरिक को 1,500 रुपये की मासिक पेंशन दी जा रही है, ताकि वे अपनी दैनिक जीवन को सम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्रता के साथ जी सकें।卐 पेंशन वितरण को निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए, मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा, 卐सभी लाभार्थियों के लिए समय पर और पारदर्शी तरीके से पेंशन वितरण सुनिश्चित करने हेतु, पंजाब सरकार ने 4,100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी बुजुर्ग नागरिक को अपनी उचित सहायता प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। कैबिनेट मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को पेंशन का समय पर और निर्बाध भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पेंशन वितरण में किसी भी प्रकार की देरी, लापरवाही या चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार के व्यापक दृष्टिकोण को उजागर करते हुए मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बुजुर्ग नागरिक पंजाब के सामाजिक विरासत, बुद्धिमत्ता और मूल्यों के संरक्षक हैं। 'रंगला पंजाब' के सपने को साकार करने के लिए उनकी सुरक्षा, सम्मान और खुशहाली अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि हर बुजुर्ग नागरिक अपनी जिंदगी बिना किसी चिंता के, सम्मान और मजबूत सरकारी सहायता के साथ व्यतीत कर सके, ताकि पंजाब खुशहाल, सुरक्षित और जीवंत बना रहे।

महाराष्ट्र दौरे से लौटी महिला पंचों-सरपंचों का पंचायत विभाग ने किया सममान

जिले के पंचायत सदस्यों ने दौरे के दौरान सहियोग दिया–बीडीपीओ

पंकज

होशियारपुर। पंजाब सरकार की तरफ से पंचायत विभाग की अगुवाई में जिले के महिला पंचायत सदस्यों को करवाए गए महाराष्ट्र दौरे के दौरान, वहां की प्रोग्रेसिव पंचायतों के बारे में जानकारी लेने वाले और इस दौरे के दौरान योगदान देने वाले पंचायत सदस्यों का बीडीपीओ ब्लॉक–2 के ऑफिस में बीडीपीओ दिलबाग सिंह, सुपरटेंडेंट अजय कुमार की अगुवाई में सममान किया गया। इस मौके पर दिलबाग सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से करवाए गए इस दौरे का मकसद जिले की महिला पंचों–सरपंचों को महाराष्ट्र की प्रोग्रेसिव पंचायतों द्वारा विकास के लिए अपनाए गए मॉडल से अवगत करवाना था और हमें बहुत खुशी है कि इस दौरे पर भेजे गए पंच–सरपंच और सेल्फ–हेल्प ग्रुप चलाने वाली महिलाओं ने वापस आकर अपने गांवों में काम करना शुरू कर दिया हैं। इस मौके पर पंचायत विभाग ने महाराष्ट्र दौरे से लौटी महिलाओं मीना रानी शेरपुर, रजवंत कौर डगाना खुर्द, रविंदर कौर बुरे जट्टां, कुलदीप कौर सतौर, हरमिंदर कौर पंडोरी बावा दास, नीलम रानी मिड्डेवाल आदि को सममानित किया। इस समय रजवंत कौर धामी और मीना रानी शेरपुर ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा आयोजित इस दौरे के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला है और आने वाले समय में पंचायत विभाग के नेतृत्व में हम अपने गांवों की नुहार बदल देंगे, उन्होंने आगे कहा कि ऐसे एक्सपोजर दौरे आने वाले समय में भी जारी रहने चाहिए और सभी को ऐसे दौरों का लाभ मिलना चाहिए। इस मौके पर परगट सिंह अकाउंटेंट, नीलम सैनी जीआरएस, आरती पंचायत सचिव आदि भी मौजूद थे।

गैंगस्टरां ते वार'-'ऑपरेशन प्रहार-2' के दूसरे दिन 1600 से अधिक व्यक्तियों को किया गिरफ्तार

12,000 से अधिक पुलिस कर्मियों ने वांछित अपराधियों से जुड़े 2706 ठिकानों पर की छापेमारी

डा. सुभाष चंद्र शर्मा

चंडीगढ़, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए शुरू की गई 'गैंगस्टरां ते वार' मुहिम के दौरान पंजाब पुलिस की टीमों ने आज 'ऑपरेशन प्रहार–2' के दूसरे दिन वांछित अपराधियों से संबंधित 2706 ठिकानों पर छापेमारी की। उल्लेखनीय है कि चल रही मुहिम ' गैंगस्टरां ते वार' में और तेजी लाते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने रविवार को वांछित अपराधियों को पकड़ने पर केंद्रित 72 घंटे का 'ऑपरेशन प्रहार–2' शुरू किया था। इस ऑपरेशन के संचालन के लिए पंजाब पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न पुलिस जिलों का व्यक्तिगत दौरा किया। इस संबंध में विवरण साझा करते हुए विशेष डीजीपी कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि ऑपरेशन 'प्रहार–2' के तहत लगभग 12,000 पुलिस कर्मियों वाली 2,000 से अधिक पुलिस टीमों ने पूरे पंजाब में वांछित अपराधियों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। ऑपरेशन प्रहार–2 के दूसरे दिन के परिणाम साझा करते हुए विशेष डीजीपी ने कहा कि कार्रवाई के दौरान 2596 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 1,634 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों में 53 भगोड़े अपराधी और 534 एहतियातन हिरासत में लिए गए व्यक्ति शामिल हैं। इसके अलावा 1,015 व्यक्तियों को पूछताछ और जांच के बाद रिहा कर दिया गया। लोग गुप्त रूप से एंटी– गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर – 93946–93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों/गैंगस्टरों के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के अपराध व अपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना/जानकारी भी साझा कर सकते हैं। इस दौरान, पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' के 346वें दिन भी जारी रखते हुए आज 215 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2.7 किलोग्राम हेरोइन, 863 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 12,040 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इससे केवल 346 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 48,866 हो गई है। 'डी–एडिक्शन' के हिस्से के रूप में, पंजाब पुलिस ने आज 27 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास के लिए राज़ी किया है।

वड़िंग ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से पंजाब के साथ हितों के टकराव पर सवाल किया

पंजाब के पानी के मुद्दे पर पंजाब भाजपा से स्थिति स्पष्ट करने को कहा, बोले- 'युद्ध नशों के विरुद्ध' अब बन गया है 'युद्ध झाड़ू के विरुद्ध', पार्टी ने जिला कांग्रेस अध्यक्षों समेत अन्य नेताओं के साथ श्रृंखलाबद्ध बैठकें कीं

एस. के. सक्सैना

चंडीगढ़, –पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पंजाब के साथ 卐हितों के टकराव卐 के मुद्दे पर सवाल किया है और भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई से पंजाब के पानियों के मसले पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है।

आज यहां कांग्रेस भवन में पार्टी की ओर से जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों, विधायकों/चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों तथा अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठकें करके भविष्य के कार्यक्रमों पर विचार–विमर्श किए गए।

इन बैठकों की अध्यक्षता पंजाब कांग्रेस के प्रभारी महासचिव भूपेश बघेल ने की और जबकि कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

बैठकों से हटकर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में, वड़िंग ने कहा कि सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री होने के नाते पंजाब से पानी की मांग कर रहे हैं। यह दोहरी नीति है, क्योंकि वह एक साथ न तो पंजाब में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं और न ही पंजाब के पानी पर अनुचित दावा कर सकते हैं।

इस मौके आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा विभिन्न जातियों और धर्मों को साधने के लिए दो उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति संबंधी खबरों पर टिप्पणी करते हुए, वड़िंग ने कहा कि पद योग्यता के आधार पर मिलने चाहिए, न कि केवल जाति या धर्म के आधार पर ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं है और वह सिर्फ किसी अन्य मंत्री की तरह ही होता है। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में कोई ताकत दिए बगैर आप की चुनावी वर्ष में अलग–अलग समुदायों और जातियों को खुश करने की कोशिश में सिर्फ एक नाटक बाजी है। उन्होंने जोर देते हुए, कहा कि सभी जातियों और समुदायों को वास्तविक अधिकार मिलने चाहिएं, ना के सिर्फ दिखावा होना चाहिए, जो आप करने का प्रयास कर रही है। जबकि नशों के खिलाफ सरकार की मुहिम 'युद्ध नशों के विरुद्ध' पर टिप्पणी करते हुए, वड़िंग ने कहा कि यह पूरी तरह विफल हो चुकी है और अब 'युद्ध झाड़ू के विरुद्ध' बन गई है। उन्होंने कहा कि यदि पंजाब से नशे खत्म हो गए होते, तो सरकार को विज्ञापनों पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती और लोग खुद ही कहते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसी तरह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राहुल गांधी पर अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर गलत जानकारी फैलाने के आरोपों पर, वड़िंग ने कहा कि शाह ने कब राहुल गांधी द्वारा कही गई सच्चाई को स्वीकार किया है? उन्होंने कहा कि पहले की तरह इस बार भी राहुल गांधी सही साबित होंगे, जब अमेरिका से होने वाले आयात से किसानों को भारी नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी द्वारा भाजपा पर उसके विधायकों को तोड़ने के आरोपों को लेकर, वड़िंग ने कहा कि यह दोनों दलों का आपसी मामला है, लेकिन आप पहले भी बिना किसी ठोस सबूत के ऐसे दावे करती रही है।

मुख्यमंत्री ने एक ही दिन में 18 जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को जारी की 1,431 करोड़ रुपये की राशि

लगभग 56 लाख 34 हजार लाभार्थियों को मिला सीधा लाभ

रमन कुमार

चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को एक ही दिन में 18 विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत करीब 1,431 करोड़ रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में जारी की। इस पहल से प्रदेश के लगभग 56 लाख 34 हजार लाभार्थियों को सीधा आर्थिक लाभ मिला है। मंगलवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जारी की गई राशि में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं, हर घर–हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर सब्सिडी और दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन शामिल है। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत आज 9,22,452 महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 193 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। अब तक इस योजना के तहत चार किस्तों में कुल 634 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत 23 साल और उससे ज़्यादा उम्र की महिलाएं हर महीने 2,100 रुपये की आर्थिक

मदद का लाभ लेने के लिए पात्र हैं, जिनके परिवार की सालाना आय एक लाख रुपये से कम है। हालांकि, अब 1 लाख 80 हजार रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र हैं, जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और जिन्होंने कक्षा 10 या 12 की बोर्ड परीक्षाओं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। या कक्षा 1 से 4 में 'निपुण भारत मिशन' के अंतर्गत कक्षा स्तर की दक्षता हासिल की है, जिन माताओं ने अपने बच्चों को कुपोषण से सफलतापूर्वक पुनर्वासित किया है। उन्होंने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के मौके पर 25 सितंबर, 2025 को लॉन्च किए गए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप के ज़रिए 10,51,029 महिलाओं ने आवेदन किया। इनमें से 9,22,452 महिलाएं पात्र पाई गई। उन्होंने कहा कि फरवरी 2026 से, हर महीने 1,100 रुपये सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किए जाएंगे, जबकि 1,000 रुपये सरकार द्वारा चलाए जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ही के दिन बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1,098 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिससे 34.14 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशन से संबंधित समस्याएं और आय आधारित पात्रता से जुड़ी शिकायते उनके संज्ञान में आई हैं। इन शिकायतों व अपीलों के समाधान तथा पात्रता के निष्पक्ष निपटान के लिए उन्होंने सभी जिलों के ए.डी.सी. को निर्देश जारी कर दिए हैं। अब वे सप्ताह में दो दिन सोमवार व वीरवार को इन मामलों का निवारण सुनिश्चित करेंगे। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर घर–हर गृहिणी योजना के तहत नवंबर और दिसंबर के लिए एलपीजी सिलेंडर रिफिल कराने वाली 12.62 लाख महिलाओं को सब्सिडी के तौर पर 38.97 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस योजना के तहत पात्र महिलाएं हर महीने 500 रुपये की सब्सिडी दर पर गैस सिलेंडर ले सकती हैं। इससे पहले, 17 जनवरी को, 6,08,842 से ज़्यादा लाभार्थियों को 18.56 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई थी। इस योजना के तहत अब तक 14.38 लाख महिलाओं को कुल 223.31 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत भी आज 36,000 लाभार्थियों को 101 करोड़ रुपये जारी किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती जी. अनुपमा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजयेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव श्री प्रवीन आत्रेय उपस्थित रहे।

जिले में अपराध पर निर्णायक प्रहार, 450 पुलिसकर्मियों की तैनाती, 63 गिरफ्तार

एडीजीपी इंटरनल सिक्योरिटी शिव कुमार वर्मा पत्रकारों को ऑपरेशन के बारे में दी जानकारी

मनदीप कौर

होशियारपुर, एडीजीपी इंटरनल सिक्योरिटी शिव कुमार वर्मा ने आज एसएसपी संदीप कुमार मलिक की मौजूदगी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि जिले में ऑपरेशन प्रहार 2.0 की शुरुआत कर दी गई है, जो 9 फरवरी से 12 फरवरी तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले 20 से 22 जनवरी तक चलाए गए ऑपरेशन प्रहार 1.0 के दौरान उल्लेखनीय सफलता मिली थी, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए थे। उसी कड़ी में अब अधिक सशक्त योजना और रणनीति के साथ ऑपरेशन प्रहार 2.0 चलाया जा रहा है। एडीजीपी वर्मा ने कहा कि इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले में सक्रिय गैंगस्टर, भगोड़े, हत्या व अन्य जघन्य अपराधों में शामिल आरोपियों की धरपकड़ कर कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है। इस अभियान के लिए 450 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है तथा 60 विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो विभिन्न पुलिस स्टेशनों और सब–डिवीजनों के अंतर्गत लगातार रेड कर रही हैं। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान बस स्टैंड, होटल, ढाबे और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है, ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा सके। अब तक जिला पुलिस 300 से अधिक स्थानों पर छापेमारी कर चुकी है, जबकि 125 संदिग्ध अपराधियों को राउंडअप किया गया है। ऑपरेशन के दौरान 03 घोषित अपराधियों (Proclaimed Offenders) सहित कुल 63 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस ने 01 पिस्टल (30 बोर), 01 देसी पिस्टल, 14 जिंदा कारतूस, 09 मोटरसाइकिल और 35 नशीली गोलियां बरामद की हैं। एडीजीपी शिव कुमार वर्मा ने विश्वास जताया कि ऑपरेशन प्रहार 2.0 के तहत आने वाले दिनों में और भी बड़ी सफलता हासिल होगी तथा जिले में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगेगा। उन्होंने आम जनता से भी पुलिस को सहयोग देने की अपील की, ताकि सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

हरियाणा में बनेगी देश की पहली 'झूला सेफ्टी पॉलिसी'-मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

सूरजकुंड झूला हादसे को लेकर सरकार बेहद गंभीर–मुख्यमंत्री

एस. के. सक्सैना

चंडीगढ़,हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार 卐झूला सेफ्टी पॉलिसी卐 बनाएगी। यह देश में अपनी तरह की पहली नीति होगी, जिसका उद्देश्य झूलों और मनोरंजन साधनों को पूरी तरह सुरक्षित बनाना है। इस पॉलिसी से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री मंगलवार को हरियाणा निवास पर पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में सूरजकुंड जैसी झूला टूटने की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार ठोस और प्रभावी कदम उठाएगी। उन्होंने सूरजकुंड में हुए हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस हादसे को सरकार बेहद गंभीरता से ले रही है। इस मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हादसे में घायल हुए सभी लोगों का इलाज चल रहा है, उनके इलाज का पूरा खर्च हरियाणा सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही गंभीर रूप से घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। हादसे में शहीद होने वाले इंस्पेक्टर जगदीश के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद पुलिसकर्मी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और आर्थिक मदद भी की जाएगी।

पड़ोसी देश द्वारा राज्य का माहौल खराब करने की रची जा रही है साजिश-राज्यपाल

डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में राज्यपाल ने ग्रामीण रक्षा समितियों के सदस्यों के साथ की बैठक

डा. सुभाष चंद्र शर्मा

फिरोज़पुर, पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने आज डिप्टी कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ग्रामीण रक्षा समितियों के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने पंजाब से नशे के उन्मूलन को लेकर समिति सदस्यों के साथ विचार–विमर्श करते हुए जहाँ उन्हें नशा–विरोधी अभियान में और अधिक उत्साह से भाग लेने के लिए प्रेरित किया, वहीं उनसे आवश्यक सुझाव भी प्राप्त किए। ग्रामीण रक्षा समिति के सदस्यों के साथ नशे पर अंकुश लगाने को लेकर हुई बैठक के दौरान राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पड़ोसी देश द्वारा नशे और हथियारों की तस्करी के माध्यम से राज्य का माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या को केवल सरकारी प्रयासों से समाप्त नहीं किया जा सकता; इसके लिए समाज के हर वर्ग—माता–पिता, शिक्षक, युवा, आम नागरिक और प्रशासन—को मिलकर सक्रिय भूमिका निभानी होगी। बैठक के दौरान राज्यपाल ने कहा कि ग्रामीण रक्षा समितियों की भूमिका नशा–विरोधी अभियान में अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्हें सशक्त होकर अपने–अपने गांवों की निगरानी करनी चाहिए। उन्होंने समिति सदस्यों से कहा कि वे अपने गांवों में पूरी तरह निगरानी रखें और यह भी ध्यान दें कि उनके गांव के युवा किस दिशा में जा रहे हैं, ताकि कोई भी युवा नशे के दलदल में न फंसे। इस अवसर पर उन्होंने इस अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से चलाने के लिए ग्रामीण रक्षा समितियों के सदस्यों से सुझाव भी लिए। उन्होंने कहा कि बेरोज़गारी और खालीपन नशे की लत के मूल कारण हैं। यदि युवाओं को रोज़गार से जोड़ा जाए, तो वे इस बुराई से बच सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक रोज़गार के अवसर सृजित किए जाने चाहिए, ताकि हमारे बच्चे नशे की लत से दूर रह सकें। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पंजाब वीरों, संतों और शहीदों की धरती है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम, देश की रक्षा और अन्न उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पंजाब की पुरानी शान और नेतृत्वकारी भूमिका को पुनः बहाल करने के लिए नशे के दुरुपयोग के विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव विवेक प्रताप सिंह, डिप्टी कमिश्नर दीपशिखा शर्मा, एस.एस.पी. भूपिंदर सिंह, ग्रामीण रक्षा समितियों के सदस्य आदि उपस्थित थे।

पंजाब पुलिस ने अमृतसर में पाक-आईएसआई की हिमायत प्राप्त आतंकी साजिश को नाकाम किया; आरडीएक्स आधारित आईईडी सहित एक व्यक्ति गिरफ्तार

पता लगने से बचने के लिए आईईडी बनाने में प्रयुक्त धातु की केसिंग की जगह इस्तेमाल किया गया पीवीसी पाइप–डीजीपी गौरव यादव

एस. के. सक्सैना

चंडीगढ़/अमृतसर, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाई गई मुहिम के दौरान, खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए, स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर ने एक आरोपी को आरडीएक्स आधारित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) सहित गिरफ्तार कर पाकिस्तान की आईएसआई समर्थित आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। यह जानकारी आज यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राहुल कुमार उर्फ गज्जू, निवासी चमरंग रोड, अमृतसर के रूप में हुई है। वह अमृतसर के एक सैलून में सहायक के रूप में काम करता है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान स्थित हैंडलरों के निर्देश पर काम करने वाला एक विदेशी हैंडलर के संपर्क में था। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी राहुल ने अपने विदेशी हैंडलर के निर्देश पर शहर के बाहरी इलाके में एक निर्धारित स्थान से खेप प्राप्त की थी। उन्होंने आगे कहा कि डिवाइस को

पीवीसी पाइप की केसिंग में छिपाया गया था ताकि इसका पता न चल सके। डीजीपी ने कहा कि आईईडी की डिलीवरी के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच जारी है। इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए एआईजी एसएसओसी अमृतसर सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि पाकिस्तान से आईईडी वाली खेप भेजे जाने की विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिलने पर पुलिस टीमों ने एक ऑपरेशन चलाया और संदिग्ध राहुल उर्फ गज्जू को आईईडी सहित गिरफ्तार कर लिया। एआईजी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी 2022 में अपने विदेशी हैंडलर के पंजाब दौरे के दौरान उसके संपर्क में आया था और दोनों एन्क्रिप्टेड मोबाइल ऐप्स के माध्यम से एक–दूसरे से संपर्क करते थे। उन्होंने कहा कि विदेशी हैंडलर ने शुरू में राहुल को काम सौंपने से पहले उसके खर्चों के लिए छोटी–छोटी रकम देकर उसे जाल में फंसाया। उन्होंने कहा कि इस मामले की आगे की जांच जारी है। इस संबंध में, थाना एसएसओसी अमृतसर में दिनांक 09.02.2026 को एफआईआर नंबर 08 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5, आर्म्स एक्ट की धारा 25 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 111 और 61(2) के तहत दर्ज की गई है।

जरनैल शाम सिंह अटारी के 180वें शहीदी दिवस पर पंजाब सरकार द्वारा नारायणगढ़ और अटारी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम

कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. द्वारा जरनैल शाम सिंह अटारी को श्रद्धांजलि

मनदीप कौर

चंडीगढ़/ अमृतसर, पंजाब सरकार द्वारा सिख कौम के महान जरनैल शाम सिंह अटारीवाला का 180वां शहीदी दिवस आज इंडिया गेट और अटारी समाधि पर पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। राज्य स्तरीय शहीदी समारोह के अवसर पर पंजाब के लोक निर्माण मंत्री सरदार हरभजन सिंह ई.टी.ओ. मुख्य अतिथि और श्री जसविंदर सिंह रमदास, हल्का विधायक अटारी तथा डॉ. जसबीर सिंह संधू, विधायक अमृतसर पश्चिमी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर इंडिया गेट के पास बने महान जरनैल शाम सिंह अटारीवाला के स्मारक पर कैबिनेट मंत्री सरदार हरभजन सिंह ई.टी.ओ., विधायक डॉ. जसबीर सिंह संधू, ब्रिगेडियर एस.एस. जामवाल, कमांडर 54 इन्फेंट्री ब्रिगेड, कर्नल सुमित शर्मा, उपायुक्त श्री दलविंदरजीत सिंह, पुलिस आयुक्त सरदार गुरप्रीत सिंह भुल्लर, एस.डी.एम. सरदार मनकंवल सिंह चाहल, कर्नल हरिंदर सिंह, कर्नल

कुलदीप सिंह ने शहीद सरदार शाम सिंह अटारीवाला की प्रतिमा पर श्रद्धांजलियां अर्पित कीं। इस अवसर पर पंजाब पुलिस के जवानों द्वारा महान जरनैल सरदार शाम सिंह अटारीवाला को हथियार उल्टे कर सलामी भी दी गई। इसके बाद अटारी स्थित सरदार शाम सिंह अटारीवाला की समाधि पर आयोजित श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के बाद धार्मिक दीवान सजाए गए। श्री दरबार साहिब के हजूरी रागी भाई गुरजीत सिंह बैंका द्वारा गुरु जस गायन किया गया और भाई गुरप्रीत सिंह भंगू के ढाडी जत्थे द्वारा जरनैल शाम सिंह अटारीवाला के जीवन और उनकी शहादत का वृत्तांत संगतों के साथ साझा किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने अटारी पहुंच कर महान जरनैल शाम सिंह को श्रद्धा के फूल अर्पित किए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सरदार हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने सरदार शाम सिंह अटारीवाला जी की समाधि पर नतमस्तक होकर उन्हें अपनी श्रद्धा और सम्मान अर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार शाम सिंह अटारीवाला म्यूजियम का दौरा भी किया। इसके बाद धार्मिक दीवान में सरदार शाम सिंह अटारीवाला को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कैबिनेट मंत्री सरदार हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि सरदार शाम सिंह अटारीवाला सिख कौम के महान जनरल थे और एंग्लो–सिख युद्ध के दौरान सभराओ की जंग में आखिरी दम तक जूझने के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरदार शाम सिंह अटारीवाला की बहादुरी और शहादत की प्रशंसा अंग्रेजों ने भी की है। उन्होंने कहा कि शहीद कौम का धरोहर होते हैं और अपने शहीदों को याद रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। सरदार हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि अटारी गांव को नया रूप दिया जाएगा ताकि रिट्रीट सेरेमनी देखने आने वाले यात्री अटारीवाला की समाधि पर आएं और अपने बच्चों को उनकी शहादत के बारे में बताएं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस तरह के कार्यक्रमों में बढ़–चढ़कर हिस्सा लें और अपने बच्चों को भी इतिहास से अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार महान शहीद सरदार शाम सिंह अटारीवाला की शहादत को नमन करती है, जिन्होंने अपनी जान देश–कौम के लिए कुर्बान कर दी। इस मौके पर सरदार शाम सिंह अटारी के परिवार के सदस्यों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों कर्नल हरिंदर सिंह अटारी, मलविंदर अटारी, बीर इंदर सिंह, महासचिव श्री हरप्रीत सिंह सिद्धू, बीबा अमितेश्वर कौर, बीबा जसप्रीत कौर, बीबा संदीप कौर, श्री दिनेश सिंह सिद्धू, इंदर जसबीर सिंह संधू लोपोके, अनंतबीर सिंह, चरणजीत सिंह, रमनदीप कौर, रवि इंदर सिंह, कर्नल गुरबंत सिंह, श्रीमती हरमन सिंह, जसकिरन कौर, रमनदीप कौर, सरपंच अटारी हरप्रीत सिंह को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सरदार हरभजन सिंह ई.टी.ओ. द्वारा प्रसिद्ध लेखिका डॉ. कुलविंदर कौर मिन्हास की पुस्तक 'सिख राज के आखिरी थंम –सरदार शाम सिंह अटारीवाला' का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सरदार हरभजन सिंह ई.टी.ओ. की धर्मपत्नी श्रीमती सुरिंदर कौर, भारतीय वायु सेना के पूर्व अधिकारी निर्मल सिंह बेदी, कर्नल कुलदीप सिंह, धन–धन बाबा दीप सिंह जी हरियाली मिशन के अध्यक्ष कंवलजीत सिंह, रछपाल सिंह, सूबेदार मेजर मनजीत सिंह, नरिंदर सिंह के अलावा बड़ी संख्या में इलाके के निवासी और विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी भी मौजूद रहे।

पंजाब के प्रयास रंग लाए; जी-4 पोटाश खोज परियोजना को मिली मंज़ूरी-बरिंदर कुमार गोयल

फ़ाजिल्का में 48 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 1903.11 लाख रुपये की लागत से किया जायेगा पोटाश सर्वेक्षण

एस. के. सक्सैना

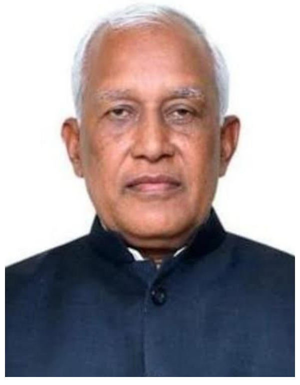

चंडीगढ़, पंजाब के खनन एवं भू–विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल द्वारा पंजाब भर के सभी खनिज समृद्ध क्षेत्रों की तत्काल पहचान करने के मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाए जाने के बाद केंद्रीय खनन मंत्रालय के राष्ट्रीय खनिज खोज एवं विकास ट्रस्ट की परियोजना सैंकशनिंग कमेटी की 9 फरवरी, 2026 को हुई बैठक में ''पंजाब के ज़िला फाजिल्का के चवाड़ियांवाली क्षेत्र में पोटाश के लिए खोज सर्वेक्षण जी–4'' शीर्षक वाली नई खोज परियोजना को मंज़ूरी दे दी गई है। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि यह परियोजना मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड द्वारा 21 महीनों की अवधि के अंदर 1903.11 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 48.0 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्वीकृत योजना के अनुसार 9 महीनों बाद परियोजना की समीक्षा की जाएगी। पहले चरण में 3200 मीटर के ग्रिड अंतराल पर 5700 मीटर की कुल ड्रिलिंग सहित छह बोरहोल किए जाएंगे। समीक्षा के बाद पहचाने गए संभावित जोनों में दूसरे चरण के तहत 1600 मीटर के ग्रिड अंतराल पर 8550 मीटर की कुल ड्रिलिंग सहित नौ अतिरिक्त बोरहोल किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि पिछले जनवरी महीने में पंजाब के खनन एवं भू–विज्ञान मंत्री बरिंदर गोयल ने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय खनिज चिंतन सम्मेलन–2026 के दौरान पंजाब में पोटाश की खोज का मुद्दा ज़ोरदार तरीके से उठाया था। उन्होंने फाजिल्का ज़िले में पोटाश के संभावित स्रोतों की पहचान का मुद्दा उठाते हुए फील्ड सीज़न 2025–26 के दौरान ड्रिलिंग और भू–वैज्ञानिक मैपिंग के कार्यों में तेज़ी लाने के लिए भी कहा था। इसी दौरान कैबिनेट मंत्री ने केंद्रीय एजेंसियों से अपील की थी कि पंजाब में पोटाश की खोज को प्राथमिकता दी जाए क्योंकि इसका सीधा संबंध देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की भलाई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने राज्य भर के खनिज समृद्ध क्षेत्रों में विश्वसनीय तरीके से खनिज सूची तैयार करने के लिए समयबद्ध कार्रवाई की मांग भी की थी। पंजाब सरकार द्वारा खोज क्षेत्र के विस्तार के बारे में अनुरोध के बाद भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने फील्ड सीज़न 2026–27 के दौरान फाजिल्का ज़िले के केरा–खेड़ा ब्लॉक और सईदवाला ब्लॉक में पोटाश के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण और कंधवाला–रामसरा ब्लॉक में प्रारंभिक खोज कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है। इस कार्यक्रम के तहत पहचानी गई 15 संभावित स्थानों पर ड्रिलिंग की जानी है। कैबिनेट मंत्री ने मांग की कि राज्य के पोटाश स्रोत आधार को मज़बूत करने के लिए सभी प्रस्तावित ब्लॉकों में कार्य, फील्ड सीज़न 2026–27 की निर्धारित समय–सीमा के अंदर पूरे किए जाएं। बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि पोटाश देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण और लाभकारी है क्योंकि इसकी लगभग 99 प्रतिशत आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी की जाती है और घरेलू खोज एवं खनन में किसी भी प्रगति से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र और दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को मज़बूती मिलेगी।

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने पटियाला के स्कूल ऑफ एमिनेंस का अचानक किया दौरा, बुनियादी ढांचे का लिया जायजा

शिक्षा मंत्री ने शिक्षा की गुणवत्ता और सुविधाओं के बारे में फीडबैक लेने के लिए विद्यार्थियों से की बातचीत

मनदीप कौर

चंडीगढ़, पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज सुबह पटियाला जिले के भादसों में स्थित स्कूल ऑफ एमिनेंस का अचानक दौरा किया, जो भगवंत मान सरकार की चल रही %पंजाब शिक्षा क्रांति% के तहत सरकारी स्कूलों में शिक्षा को मजबूत करने की दृढ़ वचनबद्धता को उजागर करता है। इस दौरे के दौरान शिक्षा मंत्री ने चल रहे बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों का जायजा लिया और शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रदान की जा रही सुविधाओं का मूल्यांकन करने के लिए विद्यार्थियों के साथ सीधे तौर पर बातचीत की। स्कूल का व्यापक दौरा करते हुए स.हरजोत सिंह बैंस ने बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने सम्बन्धित कार्यों की प्रगति का बारीकी से जायज़ा लिया। उन्होंने स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और सुविधाओं के बारे में फीडबैक लेने के लिए विद्यार्थियों के साथ बातचीत भी की। स. बैंस ने इस स्कूल में 90 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे अति– आधुनिक इन्डोर स्पोर्टस कंपलैक्स के निर्माण का भी जायज़ा लिया, जिसमें दो कबड्डी मैट और एक कुश्ती मैट सहित 2,000 लोगों के बैठने की सामर्थ्य है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा युवाओं को मानसिक और शारीरिक पक्ष से सेहतमंद बनाने के लिए शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स. हरजोत सिंह बैंस ने कहा, 卐 शिक्षा भगवंत मान सरकार की प्राथमिकता है। हमारे %स्कूल आफ एमिनेंस% केवल इमारतें नहीं है; यह भविष्य के नेताओं और पेशेवरों का आधार है। प्राईवेट स्कूलों के विद्यार्थियों की तरफ से सरकारी स्कूलों में दाख़िला लेना हमारी नीतियों और प्रदान की जा रही मानक शिक्षा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने कहा, 卐 शिक्षा के लिए फंड की कोई कमी नहीं है। हमारे विद्यार्थियों में निवेश करना सीधे तौर पर पंजाब और देश के भविष्य में निवेश करने के बराबर है। स्कूल प्रिंसिपल प्रीतइन्दर घई ने शिक्षा मंत्री को बताया कि इस शैक्षणिक वर्ष स्कूल के दाख़िलों में 11 प्रतिशत विस्तार हुआ है और 200 से अधिक विद्यार्थी प्राईवेट स्कूलों से आए है, जो कि सरकारी शिक्षा प्रणाली में अभिभावकों के बढ़ते विश्वास को दिखाता है। उन्होंने बताया कि 400 से अधिक विद्यार्थी छह स्कूल बसों के द्वारा यातायात सुविधाओं का लाभ ले रहे है, जो कि उत्तमता केंद्र के तौर पर स्कूल की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है।

डॉ. बलजीत कौर द्वारा नव-नियुक्त भलाई बोर्ड चेयरपर्सन के साथ पहली आधिकारिक बैठक; हर वर्ग के हितों की सुरक्षा सरकार की प्रमुख प्राथमिकता

मान सरकार सामाजिक न्याय और समावेशी भलाई को मजबूत करने के लिए दृढ़ता से काम कर रही है – डॉ. बलजीत कौर

डा. सुभाष चंद्र शर्मा

चंडीगढ़, मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के निर्णायक नेतृत्व में, पंजाब सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करने और पूरे राज्य में सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण के ढांचे को मजबूत करने के लिए निर्णायक, समयबद्ध और परिणाम–उन्मुख कदम उठा रही है। यह बात सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कही। पंजाब भवन में विभिन्न भलाई बोर्डों के नव–नियुक्त चेयरपर्सन के साथ पहली आधिकारिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, डॉ. बलजीत कौर ने स्पष्ट रूप से कहा कि भलाई बोर्डों को सक्रियता, जिम्मेदारी और सरकार के साथ निकट समन्वय के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने चेयरपर्सन को निर्देश दिए कि वे अपने–अपने समुदायों के मुद्दों, मांगों और प्राथमिकताओं की योजनाबद्ध तरीके से पहचान करें और यह सुनिश्चित करें कि इनका समय पर और प्रभावी प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से समाधान किया जाए। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने विभिन्न भलाई बोर्डों के चेयरपर्सन द्वारा उठाई गई समस्याओं को बहुत गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट एवं समयबद्ध निर्देश जारी किए, साथ ही नियमित अनुपालन रिपोर्ट्स की मांग भी की, जिससे देरी या प्रक्रियागत ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। डॉ. बलजीत कौर ने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार का दृष्टिकोण भलाई बोर्डों के गठन से कहीं अधिक है। हमारा उद्देश्य हर योग्य नागरिक को भलाई योजनाओं की प्रभावी, पारदर्शी और सीधी डिलीवरी सुनिश्चित करना है, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि सरकार सबके लिए न्याय, सबके लिए विकास卐 के सिद्धांत पर अटूट प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा व्यवस्था के तहत समाज के किसी भी वर्ग को उपेक्षित या हाशिए पर धकेला महसूस करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस मिशन में भलाई बोर्डों से सरकारी नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुँचाने में निर्णायक भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने हाल ही में समाज के विभिन्न वर्गों की भलाई और उन्नति को सुनिश्चित करने के लिए कई भलाई बोर्डों का गठन किया है। इनमें कम्बोज भलाई बोर्ड , बाजीगर और टपरीवास भलाई बोर्ड, ब्राह्मण भलाई बोर्ड, खत्री अरोड़ा भलाई बोर्ड , दलित विकास भलाई बोर्ड, राय सिख भलाई बोर्ड , राजपूत भलाई बोर्ड , विमुक्त जाति भलाई बोर्ड , प्रजापति भलाई बोर्ड, सैनी भलाई बोर्ड, रामगढ़िया भलाई बोर्ड, अग्रवाल भलाई बोर्ड , गुज्जर भलाई बोर्ड, बैरागी भलाई बोर्ड, स्वर्णकार भलाई बोर्ड, सैन समाज भलाई बोर्ड, पंजाब राज्य मुस्लिम विकास बोर्ड, प्रवासी भलाई बोर्ड, कनौजिया भलाई बोर्ड, मसीह भलाई बोर्ड, सूफी संत समाज भलाई बोर्ड शामिल हैं । उन्होंने आगे कहा कि ये भलाई बोर्ड अपने समुदायों को सामने आने वाली सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक चुनौतियों का आवश्यकता–आधारित मूल्यांकन करेंगे, सरकार को ठोस नीतिगत सिफारिशें सौंपेंगे और प्रशासन तथा लोगों के बीच एक मजबूत एवं जवाबदेह संस्थागत पुल के रूप में काम करेंगे। डॉ. बलजीत कौर ने आगे कहा कि यह पहल पंजाब सरकार के दृढ़ इरादे को दर्शाती है कि वह पूरे राज्य में समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और एक सद्भावपूर्ण एवं समानता वाले सामाजिक ताने–बाने को मजबूती प्रदान कर रही है। इस अवसर पर सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के प्रधान सचिव श्री वी.के. मीणा, आई.ए.एस., निदेशक श्रीमती विम्मी भुल्लर, आई.ए.एस. तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में विशेष रूप से उपस्थित थे।

एस.सी. कमीशन द्वारा भेजे गए नोटिस को प्रताप सिंह बाजवा के घरेलू कर्मचारियों ने लेने से किया इनकार-जसवीर सिंह गढ़ी

90 दिनों में दूसरी बार प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ लेना पड़ा एस.सी. कमीशन को नोटिस

पंकज

चंडीगढ़, पंजाब राज्य अनुसूचित जातियां आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस को विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा के चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 8 और सेक्टर 39 के निवास स्थानों के घरेलू कर्मचारियों ने लेने से इनकार कर दिया गया। यह जानकारी आज यहां पंजाब राज्य अनुसूचित जातियां आयोग के अध्यक्ष श्री जसवीर सिंह गढ़ी ने दी।

उन्होंने बताया कि कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. के खिलाफ की गई जातिसूचक टिप्पणी के संबंध में एस.सी. कमीशन द्वारा लिए गए स्वतरू संज्ञान नोटिस की तामील करवाने के लिए कमीशन का कर्मचारी दो बार विपक्ष के नेता के घर जा चुका है। श्री गढ़ी ने कहा कि प्रताप सिंह बाजवा को पहले तरनतारन चुनाव के दौरान नोटिस जारी किया गया था और अब फिर 90 दिनों के भीतर एक अन्य मामले में नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रताप सिंह बाजवा द्वारा अपने इस बयान के माध्यम से जहां उन्होंने अपनी जागीरू सोच का प्रदर्शन किया है, वहीं कांग्रेस पार्टी के दलित विरोधी डी.एन.ए. का चेहरा भी स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग भी दलित विरोधी मानसिकता को अपने बयानों के माध्यम से व्यक्त कर चुके हैं और कमीशन जल्द उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रहा है। श्री गढ़ी ने कहा कि हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने अपने जीवन में कठिनाइयों के बावजूद एम.ए., बी.एड. करने के बाद बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया और फिर पंजाब की बहुत ही सम्मानजनक पी.सी.एस. परीक्षा पास करके ई.टी.ओ. बनकर सेवाएं निभाईं। जिस पर दलित वर्ग और समूचे पंजाब को बहुत गर्व है। आयोग के चेयरमैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने दलितों का केवल अपमान ही किया है, जिसके अनेक सबूत हैं। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया का महान संविधान देने के बारे में बाबा साहिब डॉ. भीम राव अंबेडकर जी का रास्ता रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अनेक कोशिशें कीं। उन्होंने कहा कि बाबा साहिब की संविधान सभा में एंट्री रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अनेक कोशिशें कीं। इसके बाद जिस इलाके से बाबा साहिब चुनाव जीतकर आए, उस इलाके को 58 प्रतिशत गैर–मुस्लिम आबादी होने के बावजूद पाकिस्तान को दे दिया गया, जबकि बंटवारे के दौरान नियम था कि जिस इलाके की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी गैर–मुस्लिम होगी, वह इलाका हिंदुस्तान को दिया जाएगा। इसके अलावा दलितों को साइमन कमीशन द्वारा दिए जा रहे अधिकारों को खत्म करवाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हर तरीका अपनाया और आखिर में साइमन कमीशन की सिफारिशों को लागू होने से रोकने के लिए महात्मा गांधी ने पूना जेल में मरण व्रत रख लिया, जिसके कारण बाबा साहिब को दलितों को मिल रहे दोहरे मताधिकार को छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि आजकल कांग्रेस पार्टी के नेता यह प्रचार करते फिरते हैं कि दलितों को कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, जबकि सच्चाई यह है कि भारत के दलितों को बाबा साहिब डॉ. भीम राव अंबेडकर और भारतीय संविधान ने अधिकार दिए हैं।

उन्होंने अंत में कहा कि यदि प्रताप सिंह बाजवा में भारतीय संविधान में आस्था है तो वह एस.सी. कमीशन द्वारा दिए गए इस नोटिस के संबंध में 11 फरवरी 2026 को दोपहर 3 बजे अपना स्पष्टीकरण एस.सी. कमीशन के दफ्तर में आकर दे दें।

युद्ध नशे के विरुद्ध-मिशन स्माइल 3.0 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर हेल्प डेस्क की जिला स्तरीय शुरुआत

रमन कुमार

होशियारपुर, जिला नशा मुक्ति एवं पुनर्वास सोसायटी होशियारपुर की ओर से 卐युद्ध नशे के विरुद्ध卐 अभियान के अंतर्गत मिशन स्माइल 3.0 के तहत सार्वजिनक स्थलों पर हेल्प डेस्क की जिला स्तरीय औपचारिक शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का शुभारंभ डिप्टी कमिश्नर–कम– चेयरपर्सन जिला नशा मुक्ति एवं पुनर्वास सोसायटी होशियारपुर आशिका जैन ने डिप्टी मेडिकल कमिश्नर डॉ. स्वाति शीमार की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज जिला नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र होशियारपुर डॉ. जसलीन कौर, काउंसलर प्रशांत आदिया, काउंसलर संदीप कुमारी, साइकैट्रिक सोशल वर्कर सुखप्रीत कौर, जिला तकनीकी कोऑर्डिनेटर मनजिंदर कौर, जिला आई.टी. मैनेजर करमजीत सिंह तथा जिला मैनेजर सेवा केंद्र होशियारपुर गुरसेवक सिंह सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने कहा कि मिशन स्माइल 3.0 के अंतर्गत शुरू किए गए ये हेल्प डेस्क नशाखोरी से पीड़ित व्यक्तियों को समय पर उपचार से जोड़ने, आम जनता को नशे के दुष्प्रभावों, मानसिक स्वास्थ्य तथा उपलब्ध इलाज के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा 卐युद्ध नशे के विरुद्ध卐 अभियान के तहत गांवों में विलेज डिफेंस कमेटियां तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड डिफेंस कमेटियों का गठन किया गया है, ताकि समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयास किए जा सकें। इस प्रकार के प्रयासों से पंजाब की युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाया जा सकेगा। डिप्टी मेडिकल कमिश्नर डॉ. स्वाति शीमार ने बताया कि मिशन स्माइल पंजाब सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत जिला, उप–मंडल, नगर निगम, जिला एवं उप–मंडल अदालत परिसरों, बस स्टैंड, जिला अस्पताल, उप–मंडल अस्पताल, ओओएटी क्लीनिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, थानों एवं सरकारी कॉलेजों में हेल्प डेस्क स्थापित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर काउंसलरों ने कहा कि यह पहल 卐 युद्ध नशे के विरुद्ध卐 अभियान को मजबूती प्रदान करेगी तथा पंजाब को नशा मुक्त एवं खुशहाल बनाने की दिशा में एक प्रभावी कदम सिद्ध होगी।

'गैंगस्टरां ते वार' 'ऑपरेशन प्रहार-2' के तहत 1200 से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार

12,000 से अधिक पुलिस कर्मियों ने वांछित अपराधियों से जुड़े 2760 ठिकानों पर छापेमारी की

डा. सुभाष चंद्र शर्मा

चंडीगढ़, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के उद्देश्य से चल रही मुहिम 'गैंगस्टरां ते वार' के दौरान, पंजाब पुलिस की टीमों ने 'ऑपरेशन प्रहार–2' के पहले दिन आज वांछित अपराधियों से संबंधित 2760 ठिकानों पर छापेमारी की। उल्लेखनीय है कि चल रही मुहिम 'गैंगस्टरां ते वार' में और तेजी लाते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने रविवार को वांछित अपराधियों को पकड़ने पर केंद्रित 72 घंटे का 'ऑपरेशन प्रहार–2' शुरू किया था। इस ऑपरेशन का नेतृत्व करने के लिए पंजाब पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न पुलिस जिलों का व्यक्तिगत दौरा कर चुके हैं। इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए विशेष डीजीपी कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने कहा कि ऑपरेशन 'प्रहार–2' के तहत लगभग 12,000 पुलिस कर्मियों वाली 2,000 से अधिक पुलिस टीमों ने पूरे पंजाब में वांछित अपराधियों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। ऑपरेशन प्रहार–2 के पहले दिन के परिणाम साझा करते हुए विशेष डीजीपी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान 1895 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 1250 को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में 40 फरार अपराधी और 298 एहतियातन हिरासत में लिए गए व्यक्ति शामिल हैं। इसके अलावा 666 व्यक्तियों को जांच और पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोग गुप्त रूप से वांछित अपराधियों/गैंगस्टरों की जानकारी एंटी–गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर – 93946–93946 के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के अपराध या आपराधिक गतिविधियों की सूचना/जानकारी भी साझा कर सकते हैं। इस दौरान पुलिस टीमों ने नशे के खिलाफ अपनी मुहिम 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' को 345वें दिन भी जारी रखते हुए आज 72 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 26.4 किलोग्राम हेरोइन, 772 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 12.17 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की। इसके साथ ही मात्र 345 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 48,331 हो गई है। नशा छुड़ाऊ मुहिम के तहत पंजाब पुलिस ने आज 21 व्यक्तियों को नशा मुक्ति और पुनर्वास इलाज करवाने के लिए राजी किया है।